लखनऊ

गुरुवार, 18 जून, 2026

वर्ष : 11 । अंक: 292

मूल्य : 1 रुपये

पृष्ठ : 8

UPHIN/2014/57034

हिंदी दैनिक

आर्यावर्त क्रांति

आपके शरीर की सबसे सुंदर चीज है मन, इसे बुरे विचारों से मैला ना करें

TODAY WEATHER

DAY 41° Hi

NIGHT 29° Low

संक्षेप

उद्धव ठाकरे के सांसदों का फोन बंद, दिल्ली में एकनाथ शिंदे से मिलने की तैयारी

मुंबई। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की मुश्किलें थम नहीं रही है। पार्टी और चुनाव चिन्ह खोने के बाद अब शिवसेना (उद्धव गुट) के लोकसभा सांसद भी एकनाथ शिंदे की तरफ जाते दिख रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पार्टी के वरिष्ठ नेता कुछ लोकसभा सांसदों से फोन पर संपर्क करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके फोन बंद हैं। इस बीच, खबर आई है कि दिल्ली में 9 में से 6 सांसद बुधवार को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री शिंदे से मिल सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, उद्धव गुट के 2 सांसद दिल्ली पहुंच गए हैं, जबकि 4 अन्य सांसदों की प्रतीक्षा की जा रही है। यह समूह शिवसेना (शिंदे गुट) सांसद और शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे के आवास पर बैठक करेगा। बताया जा रहा है कि इस समूह की चर्चा में एकनाथ शिंदे भी शामिल हो सकते हैं। इस बैठक के तुरंत बाद सांसदों का समूह लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिल सकता है। महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट के बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने एक्स पर अपना सपना मनी-मनी लिखते हुए कहा, यह हैरान करने वाली और घिनौनी बात है कि खबर है कि महाराष्ट्र के सांसदों को पाला बदलने के लिए आज रात 15 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने लिखा कि उनकी पार्टी के सांसदों को 4 करोड़ तुरंत और अगले 36 महीनों के लिए 1 करोड़ प्रति महीना मिलेगा। महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर की सुगबुगाहट के बीच उद्धव ने रविवार को मातोश्री में 9 सांसदों की बैठक बुलाई थी, जिसमें 5 सांसद ओमप्रकाश राजे निम्बालकर, भाऊसाहेब वाकचौरे, नागेश बापूराव पाटिल अष्टिकर, संजय देशमुख, और संजय जाधव अनुपस्थित थे। तब पार्टी ने उनके वर्चुअल शामिल होने की बात कही थी। उद्धव ने बैठक में कहा था कि जिसे भी पार्टी छोड़कर जाना है, वो जा सकते हैं, वह दबाव नहीं डालेंगे, समय बदलेगा और उनका समय भी आएगा।

वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से कई राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट

नई दिल्ली। हाल के दिनों में बारिश और आंधी-तूफान के बाद देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर गर्मी और धुंध का मौसम है और अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आस-पास है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक नरेश कुमार के मुताबिक, 18 जून से एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर-पश्चिम भारत पर असर डाल सकता है। इसके असर से 20 और 21 जून को दिल्ली में हल्की बारिश होने की उम्मीद है। इस वजह से पूरे उत्तर-पश्चिम भारत में तापमान में काफ़ी गिरावट आने की उम्मीद है और अभी यह सामान्य से नीचे है। हालांकि, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आने से पहले तापमान बढ़ने की उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक, 17 जून को छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में, 17-18 जून को तेलंगाना में और 19-22 जून के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हीटवेव के हालात बन सकते हैं। इन इलाकों में रहने वालों को सलाह दी गई है कि वे ज्यादा देर तक धूप में न रहें और हाइड्रेटेड रहें क्योंकि ऐसे हालात में परेशानी का लेवल और गर्मी से जुड़ी बीमारियों का खतरा काफ़ी बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान और उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर-पश्चिम में हल्की बारिश का अनुमान लगाया है। हिमाचल और उत्तराखंड के लिए भारी अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि दोनों जगहों पर आज 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी-तूफ़ान आ सकते है।

मोदी शांत और संयमित, मैं वैसा नहीं... G7 में ट्रंप ने की प्रधानमंत्री की तारीफ

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज (17 जून) फ्रांस के एवियन में G7 समिट के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ट्रंप ने अचानक पीएम मोदी की तरफ इशारा करते हुए पूरी महफिल के सामने एक बड़ा बयान दे दिया। ट्रंप ने खुले दिल से स्वीकार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बेहद शांत, संयमित और बहुत प्रभावशाली हैं... मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूं। फ्रांस में G7 समिट के दौरान होने वाली इस बैठक में दोनों नेता पश्चिम एशिया के हालात, रणनीतिक रूप से अहम होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz), अमेरिका से ऊर्जा आयात और प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा कर सकते हैं। इससे पहले मंगलवार को, G7 समिट के आउटरीच सेशन के दौरान पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात हुई, उन्होंने एक-दूसरे का अभिवादन किया और संक्षिप्त बातचीत की। दोनों नेताओं की मुलाकात लगभग डेढ़ साल बाद हुई थी। भारत-अमेरिका संबंधों में तब बड़ी गिरावट आई थी जब वाशिंगटन ने भारत पर दंडात्मक टैरिफ लगाए और राष्ट्रपति ट्रंप ने मई 2025 में भारत-पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव को कम करने में अपनी भूमिका को लेकर विवादास्पद दावे किए थे। पिछले महीने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की भारत यात्रा के बाद, दोनों पक्ष द्विपक्षीय संबंधों को फिर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि, ओमान के तट पर एक मर्चेंट जहाज पर हुए हमले में पिछले हफ्ते तीन भारतीय नाविकों की मौत के बाद रिश्तों में फिर से तनाव आ गया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मन चांसलर के साथ द्विपक्षीय बैठक की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ से मुलाकात की। इस साल दोनों नेताओं के बीच यह दूसरी बैठक थी। नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और भारत-जर्मनी रणनीतिक साझेदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। यह गति चांसलर की भारत यात्रा और इस साल की शुरुआत में भारत-यूरोपीय संघ FTA वार्ता के सफल समापन के कारण आई है।

राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला, बोले- युवाओं के सपनों से हो रहा खिलवाड़

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर युवाओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि देश के हर युवा का भविष्य सुरक्षित करना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन मौजूदा सरकार की नीतियों के कारण करोड़ों युवाओं के सपने टूट रहे हैं।

राहुल गांधी ने कहा कि पेपर लीक, परीक्षा प्रबंधन में खामियां, भर्तियों का रद्द होना, बढ़ती फीस, निजीकरण और विभिन्न घोटालों ने युवाओं की परेशानियां बढ़ा दी हैं। उनका आरोप है कि इन समस्याओं के कारण लाखों छात्र और नौकरी की तैयारी कर रहे युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं।

कांग्रेस नेता ने युवाओं और खासकर जेन-जी पीढ़ी के नाम जारी संदेश में कहा कि देश का भविष्य युवाओं के हाथ में है। उन्होंने बताया कि राजस्थान के कोटा में आयोजित होने वाली 'छात्रों की गूंज' महारैली में वह इन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और युवाओं की आवाज को बुलंद करेंगे।

युवाओं से की अपील

राहुल गांधी ने युवाओं से 17 जून को होने वाली महारैली में शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश के हर गली, कस्बे और शहर से उठ रही छात्रों की आवाज को कोटा में एक मजबूत हुंकार में बदलने का समय आ गया है। रैली में शिक्षा, रोजगार और युवाओं से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

अब छोड़ेंगे नहीं... शिव सेना उद्धव गुट के बागियों को संजय राउत की धमकी, ऑन कैमरा दी गाली

मुंबई, एजेंसी। शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ने पार्टी में फूट की बढ़ती अटकलों के बीच बागी सांसदों पर तीखा हमला किया। उन्होंने उन पर धोखा देने का आरोप लगाया और उद्धव ठाकरे गुट के प्रति उनकी वफादारी पर सवाल उठाए। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, राउत ने उनसे अरविंद सावंत और अनिल देसाई की बातों पर ध्यान देने को कहा और राजाभाऊ वाजे की निष्ठा की तारीफ की। बताया जाता है कि पार्टी के नौ सांसदों में से ये तीन ही सांसद हैं जो उद्धव ठाकरे का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अब आप बस सुनें और समझें कि अरविंद सावंत और अनिल देसाई क्या कह रहे हैं। हमें राजाभाऊ वाजे की निष्ठा और ईमानदारी को भी देखना चाहिए।

राउत ने पार्टी के प्रति वाजे की बार-बार जताई गई वफादारी का ज़िक्र करते हुए कहा कि जब से वे (राजाभाऊ वाजे) ट्रेन से उतरे हैं, तब से वे कह रहे हैं कि वे उद्धव ठाकरे सेना के साथ हैं। इस बात पर ज़ोर देते हुए कि राजनीतिक पद अस्थायी होते हैं लेकिन संगठन के प्रति वफादारी स्थायी होती है, राउत ने कहा MLA और MP के पद आते-जाते रहते हैं। आज हम कानून बनाने वाले हैं, कल नहीं रहेंगे। लेकिन इस समूह ने हमें जो कुछ भी दिया है, उसे हम भूल नहीं सकते। बालासाहेब ठाकरे ने हमें बच्चों की तरह पाला-पोसा, उद्धव ने हमें भाइयों की तरह प्यार किया। इसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़कर जा रहे लोगों को गालियां देते हुए कहा, ये साले... जो जा रहे हैं। फिर उन्होंने मीडिया वालों से कहा कि वे उनकी गालियों को सेंसर न करें।

रामनगरी में गोरखधंधा... चंदा विवाद पर अखिलेश ने बीजेपी को घेरा, कहा- सीसी मतलब चंदा चोरी

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राम मंदिर चंदा चोरी विवाद पर यूपी सरकार को घेरा है। उन्होंने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बीजेपी के लिए धर्म का मतलब धन है। चुनाव में बेइमानी हुई थी। वहां सीसीटीवी नहीं मिले थे। मंदिर में भी नोटों की गिनती के दौरान सीसीटीवी नहीं थे। सीसी का राज खुल गया। इसका मतलब है चंदा चोरी (सीसी)।

अखिलेश ने कहा कि हमने समय-समय पर सरकार को चेताया कि कैसे जमीन का घोटाला हुआ। लोगों को सताया गया। दुकानें छीनी गईं बुलडोजर चला। एयरपोर्ट में जमीन देने वाले लोगों को बाजार भाव नहीं दिया गया। सपा प्रमुख ने कहा कि इनकी सरकार में अमीर अमीर हो रहा है और गरीब गरीब हो रहा है। गैस सिलिंडर आज महंगा हो गया है।

अखिलेश ने कहा कि जैसा खुलासा हो रहा है वो सबके सामने है। मथुरा जन्मभूमि मामले में चंदे की गड़बड़ी पर उन्होंने कहा कि जनता पूछती है तो ये हिसाब क्यों नहीं देते हैं। सरकार के कई साथियों की जमीन कब्जा की। 8 एकड़ जमीन ली लेकिन मुआवजा नहीं दिया गया। हम सभी साधु संतों का सम्मान करते हैं। हमारा धर्म का रास्ता सत्य का रास्ता है। हमारे PDA का मतलब प्रेम दया अपनापन भी है। हमारा मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। राम मंदिर को लेकर दिए गए बृजभूषण शरण सिंह के बयान पर बोले मुझे उनके बयान की जानकारी नहीं है। पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह ने अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे की चोरी मामले में गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर आंदोलन से जुड़े लोगों की चिंताओं को सरकार गंभीरता से ले और 'बिना धुएं के आग नहीं लगती'। सिंह ने कहा कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में SIT की जांच लगातार तीसरे दिन जारी है। जांच टीम ने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, व्यवस्थापक गोपाल राव सहित कई कर्मचारियों से पूछताछ की। अब तक 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। एसआईटी दानपात्रों से लेकर रिकॉर्ड तक की जांच कर रही है। आज तीसरे दिन भी एसआईटी की जांच चल रही है।

नीट परीक्षा से पहले लगे प्रतिबंध के खिलाफ टेलीग्राम पहुंची दिल्ली हाई कोर्ट

नई दिल्ली, एजेंसी। टेलीग्राम ने भारत सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। केंद्र ने नीट (यूजी) 2026 की दोबारा परीक्षा से पहले 22 जून तक देश में टेलीग्राम की सेवाओं पर रोक लगाने का फैसला किया था। इस मामले की सुनवाई जस्टिस तेजस करिया की अवकाशकालीन पीठ के सामने रखी गई, जिसने इसे तुरंत सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। बता दें, नीट की दोबारा परीक्षा 21 जून को आयोजित की जानी है।

केंद्र सरकार ने यह फैसला राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) और शिक्षा मंत्रालय की सिफारिश पर लिया है। अधिकारियों का कहना है कि कुछ समूह टेलीग्राम का इस्तेमाल करके छात्रों और अभिभावकों को कथित पेपर लीक और परीक्षा से जुड़ी भ्रामक जानकारी के जरिए गुमराह कर रहे थे। सरकार का मानना है कि परीक्षा के दौरान इस तरह की गतिविधियों को रोकना जरूरी है, ताकि उम्मीदवार बिना किसी भ्रम के निष्पक्ष माहौल में परीक्षा दे सकें। सरकार ने टेलीग्राम को भारतीय यूजर्स के लिए 30 जून तक पुराने मैसेज में बदलाव करने की सुविधा बंद करने का निर्देश भी दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ लोग पहले सामान्य मैसेज पोस्ट करते थे और बाद में उनमें बदलाव करके प्रश्नपत्र या अन्य सामग्री जोड़ देते थे। इसके बाद पुराने समय के स्क्रीनशॉट दिखाकर पेपर लीक होने का दावा किया जाता था। इस तरह की भ्रामक गतिविधियों को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। अधिकारियों के अनुसार, टेलीग्राम पर कई ऐसे चैनल सक्रिय थे जो कथित तौर पर परीक्षा के प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने का दावा कर रहे थे।

नीट परीक्षा को लेकर नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार

नई दिल्ली, एजेंसी। नीट परीक्षा को लेकर नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। नीट पेपर लीक मामले के बाद 21 जून को फिर से नीट यूजी परीक्षा होने जा रही है, जिसे लेकर एक याचिका दाखिल हुई। याचिका में कहा गया कि पेपर लीक के आरोप के बाद करीब 22 लाख छात्रों को नए सिरे से परीक्षा देने के लिए कहना गलत है। गड़बड़ी कुछ लोगों और परीक्षा केंद्रों तक सीमित थी। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया और कहा कि नीट से जुड़े मामले दूसरी बेंच सुन रही है। यह केस भी उसी बेंच के सामने जुलाई के महीने में लगेगा। इस साल तीन मई को हुई नीट यूजी परीक्षा को पेपर लीक की जानकारी सामने आने के बाद 12 मई को रद्द कर दिया गया था। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल हुई हैं, जिनमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को भंग करने या उसका बुनियादी पुनर्गठन करने जैसी कई मांग की गई हैं। इन याचिकाओं पर जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच सुनवाई कर रही है। 1 जून को भी एक याचिका दाखिल हुई थी, जिसमें पेपर-पेन के बजाय कम्प्यूटर बेस्ट टेस्ट (CBT) मोड में परीक्षा आयोजित किए जाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने यह अर्जी खारिज करते हुए कहा था कि अब परीक्षा में काफी कम समय बचा है। कोर्ट ने परीक्षा अधिकारियों पर मौजूदा दबाव और व्यावहारिक दिक्कतों का हवाला दिया।

नीट यूजी री-एग्जाम से पहले राहुल गांधी की रैली, भाजपा बोली- छात्रों को भटकाने की साजिश

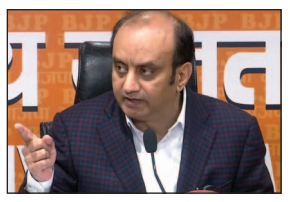

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राजस्थान के कोटा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की प्रस्तावित 'इको ऑफ़ स्टूडेंट्स' रैली की आलोचना की और उन पर अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए व्यवधान पैदा करने की कोशिश का आरोप लगाया। त्रिवेदी ने बुधवार को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बातें कहीं। उन्होंने 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की दोबारा परीक्षा से कुछ दिन पहले यह कार्यक्रम आयोजित करने के लिए गांधी की आलोचना की और कहा कि नीट परीक्षा तीन दिन बाद फिर से होने वाली है... जहाँ सरकार संवेदनशीलता दिखा रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी संवेदनशीलता के बजाय चालाकी दिखा रहे हैं। त्रिवेदी ने सवाल करते हुए कहा कि मैं उनसे पूछना चाहता हूँ: परीक्षा से ठीक पहले के 72 घंटों में, जब किसी उम्मीदवार को पूरी एकाग्रता के साथ अंतिम चरण की तैयारी करनी चाहिए, तब आप ऐसे कार्यक्रम आयोजित करके छात्रों को मानसिक रूप से परेशान क्यों कर रहे हैं। राजनीति के लिए तो कई मौके मिलेंगे, यह 21 तारीख के बाद भी की जा सकती है।

चिंताजनक : मानसिक बीमारियां बनीं आत्महत्याओं की सबसे बड़ी वजह, 14 हजार से अधिक लोगों ने दी जान

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत में मानसिक स्वास्थ्य का संकट लगातार गहराता जा रहा है। वर्ष 2024 में बीमारी से जुड़ी वजहों के कारण 30,617 लोगों ने आत्महत्या की। इनमें सबसे बड़ा हिस्सा मानसिक बीमारियों का रहा। कुल 14,305 लोगों ने मानसिक रोगों से जुड़ी परेशानियों के चलते आत्महत्या की, जो बीमारीजनित आत्महत्याओं का 47 प्रतिशत है। यह संख्या पिछले वर्ष के 13,978 मामलों से अधिक है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के अनुसार बीमारी से जुड़ी आत्महत्याओं में मानसिक बीमारियों का योगदान सबसे अधिक रहा। कुल बीमारीजनित आत्महत्याओं में लगभग हर दूसरी मौत मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ी थी। वहीं पुरानी और गंभीर शारीरिक बीमारियां भी आत्महत्या का एक प्रमुख कारण बनी रहीं। मानसिक अवसाद, चिंता विकार, गंभीर मनोवैज्ञानिक तनाव और अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित कर रही हैं।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का क्या है कहना?

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे समय तक बीमारी झेलने वाले लोगों में अवसाद और निराशा का खतरा बढ़ जाता है, जिससे आत्महत्या का जोखिम भी बढ़ सकता है। राज्यवार आंकड़े बताते हैं कि बीमारी के कारण होने वाली आत्महत्याओं का बोझ विभिन्न राज्यों में अलग-अलग है। तमिलनाडु में 5,847, महाराष्ट्र में 3,400 और मध्य प्रदेश में 3,254 मामले सामने आए। तेलंगाना में यह संख्या 2,209 और गुजरात में 2,011 रही। कई राज्यों में मानसिक बीमारियों का योगदान बीमारीजनित आत्महत्याओं के मुकाबले अधिक रहा।

कैंसर और नशे से जुड़े मामले कम

बीमारीजनित आत्महत्याओं में कैंसर, नशे की लत और अन्य विशिष्ट रोगों से जुड़े मामलों का प्रतिशत मानसिक बीमारियों और दीर्घकालिक रोगों की तुलना में काफी कम रहा। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि कई मामलों में मानसिक और शारीरिक समस्याएं एक-दूसरे से जुड़ी होती हैं, इसलिए वास्तविक प्रभाव कहीं अधिक व्यापक हो सकता है।

अभिषेक बनर्जी से चार दिन में 31 घंटे की पूछताछ के बाद दो और एफआइआर दर्ज, 550 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार का है मामला

कोलकाता, एजेंसी। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब 550 करोड़ रुपये के कथित भ्रष्टाचार के मामले में अभिषेक के खिलाफ उनके संसदीय क्षेत्र डायमंड हार्बर में दो एफआइआर दर्ज कराई गई है।

पहली एफआइआर 300 करोड़ रुपये की मिट्टी चोरी के आरोप में दक्षिण 24 परगना के कालीतला थाने में दर्ज कराई गई है। दूसरी एफआइआर जिले के विष्णुपुर थाने में चक्रवात एंफन की राहत सामग्री में 250 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार के आरोप में दर्ज कराई गई है। एफआईआर में अभिषेक के निजी सचिव सुमित राय तथा तत्कालीन ब्लाक स्तर के कई प्रशासनिक अधिकारियों के भी नाम हैं। भाजपा नेता अभिजीत दास ने यह एफआइआर दर्ज कराई है। एफआइआर में कई गैर जमानती धाराएं भी लगाई गई हैं। बता दें कि विभिन्न मामलों में अभिषेक बनर्जी से लगातार पूछताछ की जा रही है। विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में सीआइडी ने मंगलवार को उनसे कोलकाता स्थित भवानी भवन में साढ़े छह घंटे पूछताछ की। यह लगातार तीसरा दिन रहा जब किसी जांच एजेंसी ने अभिषेक से किसी मामले में पूछताछ की है।

शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में पूछताछ जारी

इसके अलावा सोमवार को शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी के अधिकारियों ने उनसे 11 घंटे तक पूछताछ की थी। इससे पहले, रविवार को विधानसभा में तृणमूल विधायकों के जाली हस्ताक्षर मामले में सीआइडी अधिकारियों ने उनसे साढ़े आठ घंटे तक पूछताछ की थी। इसी मामले में गत बुधवार को उनसे साढ़े पांच घंटे पूछताछ हुई थी।

नहर में कूदा प्रेमी युगल, प्रेमिका को बचाया, युवक की तलाश कर रही एनडीआरएफ की टीम

आर्यावर्त संवाददाता

शिवालाकलां (बिजनौर)। रामगंगा पोषक नहर में प्रेमी युगल ने छलांग लगा दी थी। उन्हें कूदता देख आसपास के लोगों ने शोर मचाया, लेकिन दोनों पानी में बहने लगे। पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय गोताखोरों की मदद से प्रेमिका को बाहर निकाल लिया। उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं, प्रेमी का अभी पता नहीं लग सका है।

मुरादाबाद निवासी बिलाल को तलाशने के लिए एसडीआरएफ टीम को लगाया गया है। बुधवार सुबह से ही टीम मोटर बोट के सहारे उसकी तलाश में लगी है। हालांकि, मंगलवार रात अंधेरा होने के चलते सर्च अभियान नहीं चल सका था।

मुरादाबाद के सिविल लाइंस निवासी 25 वर्षीय बिलाल की रिश्तेदारी बिजनौर के गांव मंझौला बिल्लौच में है। काफी समय से बिलाल का प्रेम प्रसंग रिश्तेदार की बेटी शादमा से चल रहा है। दोनों चोरी छिपे मिलते थे। जब दोनों के परिवार वालों को इसका पता चला तो उन्होंने विरोध किया। दोनों के परिवार वाले शादी के लिए नहीं माने, तो मंगलवार शाम करीब पांच बजे दोनों गांव मंझौला बिल्लौच के पास नहर के पास पहुंचे। स्थानीय लोगों के अनुसार कुछ देर उन्होंने बात की।

उसके बाद पुल से नहर में छलांग लगा दी। इस समय में नहर में पानी लबालब बह रहा है। कुछ ही देर में दोनों पानी में डूबने लगे। आसपास के लोग मौके पर दौड़े और पुलिस को सूचना दी। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से प्रेमिका को तो बाहर निकाल लिया गया, लेकिन प्रेमी तेज बहाव में बह गया।

प्रेमिका को सीएचसी नूरपुर में भर्ती गया, उपचार के बाद उसको घर भेज दिया गया। सीओ देश दीपक सिंह ने बताया कि प्रेमी युगल आपस में रिश्तेदार हैं। दोनों के स्वजन उन्हें मिलने नहीं दे रहे थे, इसी दबाव में दोनों ने यह कदम उठाया है। लड़की अब ठीक है। जबकि, बिलाल की तलाश के लिए एसडीआरएफ को बुलाया गया है। उधर बिलाल के स्वजन नहर किनारे उसके सकुशल बरामद होने की दुआ कर रहे हैं।

आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। आबकारी आयुक्त के आदेशानुसार चलाए जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत बुधवार को सुल्तानपुर जनपद में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया। जिलाधिकारी सुल्तानपुर एवं उप आबकारी आयुक्त अयोध्या प्रभार के निर्देश तथा जिला आबकारी अधिकारी के निर्देशन में कार्रवाई की गई।

अभियान के दौरान आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-1 रण विजय सिंह एवं आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-5 नेहा श्रीवास्तव के नेतृत्व में टीम ने स्टाफ के साथ थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के ग्राम बल्लीपुर तथा थाना धनपतगंज क्षेत्र के ग्राम मायंग में दबिश दी। कार्रवाई के दौरान कुल 04 अभियोग पंजीकृत किए गए तथा 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। टीम ने मौके से करीब 45 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की। इसके अलावा लगभग 750 किलोग्राम लहन भी बरामद किया गया, जिसे नियमानुसार मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। अभियान के दौरान क्षेत्र में संचालित आबकारी दुकानों का भी निरीक्षण किया गया। दुकानों में उपलब्ध स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया गया तथा गुप्त रूप से टेस्ट परचेज कर बिक्री व्यवस्था की जांच की गई। इसके साथ ही कबाड़ियों की दुकानों और ईंट-भट्ठों पर भी गहन चेकिंग अभियान चलाया गया। आबकारी टीम ने ग्रामीणों को अवैध शराब के सेवन और निर्माण से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करते हुए सतर्क रहने की अपील की। इस अभियान में प्रधान आबकारी सिपाही साकेत राय, विष्णु प्रकाश दीक्षित तथा आबकारी सिपाही मोहम्मद इरफान, सूबेदार यादव और अभिनव सिंह शामिल रहे।

परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई, 4 अवैध बसें सीज, 9 के चालान

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। परिवहन विभाग ने मंगलवार को अवैध रूप से संचालित बसों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की। जांच में सामने आया कि कुछ बस संचालक ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट का गलत इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए सीट बुकिंग कर बसों का संचालन सामान्य रूट बसों की तरह कर रहे थे।

लगातार मिल रही शिकायतों के बाद विभाग की प्रवर्तन टीम ने जिले के विभिन्न इलाकों में व्यापक चेकिंग अभियान चलाया। यह कार्रवाई लोहरामऊ बाईपास, पयागीपुर चौराहा, अमहट चौराहा, गुप्तारगंज और सेमरी क्षेत्र में की गई। जांच के दौरान परमिट की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर 4 बसों को तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया गया, जबकि 9 बसों का चालान किया गया। इसके अलावा मोटर वाहन अधिनियम और केंद्रीय मोटरयान नियमों के तहत 15 अन्य वाहनों पर भी कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया। बस चालकों को सुरक्षित ड्राइविंग के लिए सलाह दी गई, वहीं रॉन्ग साइड वाहन चलाने वालों और बिना हेलमेट दोपहिया चलाने वालों को रोककर चेतावनी और काउंसलिंग दी गई। इस अभियान में परिवहन और यातायात विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम मौजूद रही, जिसने नियमों के पालन और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

नोएडा की महागुन सोसाइटी में तेज रफ्तार का कहर, पार्किंग में मां-बेटी को रौंदा...

आर्यावर्त संवाददाता

नोएडा। नोएडा शहर में एक बार फिर तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है। नोएडा की महागुन मिराबेला सोसायटी की पार्किंग में सोमवार देर रात एक तेज रफ्तार होंडा अमेज कार ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर महिला और उसकी 5 साल की बेटी को टक्कर मार दी। हादसा इतना जोरदार था कि दोनों करीब 10 मीटर दूर जाकर गिरीं। घटना सेक्टर-113 थाना क्षेत्र के तहत आने वाले सेक्टर-79 की महागुन मिराबेला सोसायटी की है।

घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि बच्ची को भी चोटें आई हैं। हादसे के समय महिला अपने पति और बेटी के साथ कार में सामान निकाल रही थी। तभी बेसमेंट पार्किंग में तेज रफ्तार से आई कार ने दोनों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने शोर मचाया और तुरंत मदद के लिए पहुंचे।

आरोपी गिरफ्तार, मेडिकल जांच में शराब की पुष्टि नहीं

सेक्टर-113 थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित परिवार की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी चालक को हिरासत में ले लिया गया है। मेडिकल जांच में चालक के शराब पीने की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं सोसायटी के लोगों का आरोप है कि पार्किंग क्षेत्र में वाहनों की रफ्तार को लेकर लापरवाही बढ़ती जा रही है। पार्किंग में दो घुमावदार मोड़ हैं और यहां 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति सीमा तय है, लेकिन आरोपी की कार करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थी।

कार के नीचे फंसी रही महिला

जानकारी के अनुसार, सोसायटी निवासी अरुण शर्मा अपनी पत्नी कृतिका और बेटियों के साथ रहते हैं। अरुण नोएडा की एक आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। सोमवार रात परिवार पार्किंग में खड़ी कार से सामान निकाल रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार कार ने कृतिका और उनकी छोटी बेटी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बच्ची कार के नीचे आ गई। उसे तुरंत बाहर निकाल लिया गया, लेकिन कृतिका कार के नीचे फंस गईं। लोगों ने इकट्ठा होकर कार को उठाया और करीब 4 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद महिला को बाहर निकाला। इसके बाद मां-बेटी को फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक बच्ची को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि कृतिका की पसलियों में फ्रैक्चर, सिर में चोट और कंधे में गंभीर चोट आई है। उनका इलाज जारी है।

अयोध्या में सीबीआई टीम का छापा, वित्त एवं लेखा विभाग अमेठी में करोड़ों के घोटाले में पड़ताल

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

अयोध्या। अमेठी में वित्त एवं लेखा विभाग में करोड़ों के घोटाले की जांच कर रही सीबीआई की टीम ने बुधवार को सुबह अयोध्या सहित अन्य नगरों में छापा मारा। राम नगरी में सीबीआई की टीम के इस छापे पर खलबली मच गई और लोगों ने सोचा की राम मंदिर में चढ़ावा को लेकर टीम पड़ताल कर रही है।

सीबीआई की टीम ने कोर्ट के आदेश पर अमेठी में वित्त एवं लेखा विभाग में करोड़ों के घोटाले को लेकर अयोध्या के साथ लखनऊ, प्रतापगढ़ और कुशीनगर में एक साथ छापेमारी की।

अयोध्या में टीम सुबह सात बजे पहुंची और कोतवाली नगर के देवकाली पुलिस चौकी के निकट पवन कुमार मालवीय के घर पड़ताल की। टीम ने आठ बजे तक पड़ताल समाप्त कर दी। सीबीआई की डीआईजी शिवानी तिवारी के निर्देशन में टीम ने अयोध्या में छापेमारी की।

निकाह में खाना पड़ गया कम, आपस में भिड़ गए बाराती-घराती... दूल्हे को ही पीट डाला, फिर लिखित समझौते के बाद विदा हुई दुल्हन

आर्यावर्त संवाददाता

मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक निकाह समारोह अचानक जंग के मैदान में तब्दील हो गया। मूंढापांडे थाना इलाके के खबड़िया भूड़ गांव में बारात के दौरान भोजन कम पड़ने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते सामान्य नोकझोंक ने एक बड़ा रूप अख्तियार कर लिया। माहौल इतना गरमा गया कि विवाह स्थल पर मौजूद लोग एक-दूसरे पर टूट पड़े और लात-घूंसों के साथ-साथ कुर्सियां भी फेंकी जाने लगीं। इस अफरा-तफरी के बीच खुद दूल्हा और उसका सगा भाई गंभीर रूप से चोटिल हो गए।

जानकारी के अनुसार, खबड़िया भूड़ गांव के रहने वाले छोटे ने अपनी बेटी नगीना का रिश्ता मदनापुर (होलपुर) के निवासी अरमान से तय किया था। शादी के कार्यक्रम के अनुसार, दोपहर को दूल्हा अरमान धूमधाम के साथ अपनी बारात लेकर लड़की वालों के दरवाजे पर पहुंचा था। वधु पक्ष की ओर से बारातियों के स्वागत-सत्कार और खान-पान के विशेष इंतजाम किए गए थे। लेकिन निकाह की शुरुआती रस्मों के बीच ही कुछ मेहमानों ने शिकायत की कि उन्हें भोजन नहीं मिल सका है। असल में, लड़की वालों के अनुमान से कहीं ज्यादा संख्या में बाराती शादी में शामिल होने पहुंच गए थे, जिसकी वजह से तैयार किया गया भोजन कम पड़ गया था। जब खाने की किल्लत की बात सामने आई, तो दुल्हन के परिवार वालों ने तुरंत नया भोजन बनवाने का आश्वासन दिया था। मगर इस बीच दोनों तरफ के कुछ उत्साही और गुस्सैल लोग आपस में उलझ गए। बात बढ़ने पर मारपीट शुरू हो गई, जिसमें दूल्हा अरमान और उसका भाई सलमान जख्मी हो गए। शादी के जश्न में इस तरह का बवाल देखकर आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया और तुरंत पुलिस को मामले की जानकारी दी गई।

पुलिस ने संभाला मोर्चा, समझौते के बाद हुई विदाई

विवाह में विवाद की सूचना मिलते ही मूंढापांडे थाना पुलिस भारी बल के साथ मौके पर पहुंची और विवाद कर रहे लोगों को समझा-बुझाकर स्थिति पर नियंत्रण पाया। हंगामे को लेकर पुलिस ने मौके से दूल्हे के पिता सहित चार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की। हालांकि, इस पूरे ड्रामे के बाद दोनों पक्षों के बुजुर्गों और जिम्मेदार लोगों ने सूझबूझ दिखाई। आपस में बैठकर मामले को सुलझाया गया और दोनों पक्षों के बीच एक लिखित समझौता हुआ। इसके बाद ही निकाह की बची हुई रस्में पूरी की जा सकीं और आखिरकार भारी पुलिस बल की मौजूदगी में दुल्हन को सुरक्षित विदा किया गया।

टिकट में वसूले जाने वाले अतिरिक्त शुल्क के बावजूद यात्री पानी के लिए मोहताज

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। परिवहन निगम द्वारा यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के दावों की हकीकत सुल्तानपुर डिपो में पूरी तरह से दम तोड़ती नजर आ रही है। निगम द्वारा यात्रियों के टिकट में अतिरिक्त श्यात्री सुविधा शुल्क वसूला जाता है, जिसका मकसद डिपो परिसर में साफ-सफाई, शुद्ध पेयजल और धूम्रपान निषेध वातावरण सुनिश्चित करना है। लेकिन इसके बावजूद यात्रियों को बुनियादी सुविधाओं के नाम पर सिर्फ निराशा ही हाथ लग रही है। सामाजिक संस्थाओं के प्रयासों पर भी निगम की उदासीनता यात्रियों को भीषण गर्मी और प्यास से बचाने के लिए रोटरी क्लब जैसी सामाजिक संस्थाओं ने डिपो परिसर में शुद्ध पेयजल के लिए वाटर कूलर लगवाया था। लेकिन निगम की बेरुखी और लापरवाही के कारण इसका रखरखाव शून्य हो गया है। स्थिति यह है कि आए दिन यात्रियों को पानी के लिए दर-दर भटकना पड़ता है। कभी कूलर की टोंटी तोड़ दी जाती है, तो कभी पूरा सिस्टम ही खराब पड़ा रहता है, जिसके कारण यात्रियों को अंततः मजबूरन बाजार से महंगे दाम पर पानी खरीदकर अपनी प्यास बुझानी पड़ती है।अधिकारियों की चुप्पी पर उठ रहे सवालयात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं को लेकर जब भी डिपो के जिम्मेदार अधिकारियों से बात करने की कोशिश की जाती है, तो स्टेशन अधीक्षक से लेकर एआरएम (सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक) तक इस मुद्दे पर बोलने से कतराते हैं। यह मौन कई गंभीर सवाल खड़े करता है। यात्रियों का आक्रोश दैनिक और आम यात्रियों का सीधा आरोप है कि जब निगम हमसे हर टिकट में यात्री सुविधा के नाम पर अलग से धन वसूल रहा है।

पेड़ पर दुपट्टे के फंदे से लटका मिला किशोरी का शव, आत्महत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस

आर्यावर्त संवाददाता

पीलीभीत। पीलीभीत के दियोरिया कोतवाली क्षेत्र के गांव जादौपुर पट्टी में बुधवार सुबह 17 वर्षीय किशोरी का शव जामुन के पेड़ पर फंदे से लटका मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। पुलिस की प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का बताया गया है। हालांकि मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा।

जानकारी के अनुसार गांव जादौपुर पट्टी निवासी रामचंद्र शर्मा ने बताया कि उनकी 17 वर्षीय पुत्री वर्षा रात में घर ही सोई थी। रात में किसी समय वह घर से चली गई। उस समय परिवार के सदस्य गहरी नींद में सो रहे थे। काफी देर बाद जब परिजन जागे तो वर्षा घर में नहीं मिली। इसके बाद परिवार के लोग उसकी तलाश में जुट गए। इसी बीच सुबह टहलने निकले कुछ ग्रामीणों ने गांव से करीब एक किलोमीटर दूर पैनियां मार्ग स्थित तालाब के पास जामुन के पेड़ पर किशोरी का शव चुनरी के फंदे से लटका देखा। यह खबर गांव पहुंचते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर पहुंचे परिजनों ने शव की पहचान वर्षा के रूप में की।

आत्महत्या का कारण नहीं बता सके परिजन

घटना की सूचना मिलते ही दियोरिया कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। परिजनों ने पुलिस को लिखित रूप से बताया है कि वर्षा ने आत्महत्या की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में भी मामला आत्महत्या का प्रतीत हुआ है। हालांकि किशोरी द्वारा यह कदम उठाने के पीछे क्या कारण रहे, इसका अभी पता नहीं चल सका है। क्षेत्राधिकारी विधि भूषण मौर्य ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी।

कथित अपहरण, बलात्कार एवं धर्मांतरण के मामले में अभियुक्त को न्यायालय से मिली राहत

सुल्तानपुर। जनपद सुल्तानपुर के एफ.टी.सी.-1 न्यायालय ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64, 87 तथा उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/5(1) के अंतर्गत दर्ज कथित अपहरण, बलात्कार एवं धर्मांतरण के मामले में अभियुक्त की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उसे जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश पारित किया। अभियुक्त की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद आरिफ ने प्रभावी एवं तथ्यपरक पैरवी करते हुए न्यायालय के समक्ष तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्त को दुर्भावनावश झूठे एवं मनगढ़ंत आरोप लगाकर मुकदमे में फंसाया गया है। बचाव पक्ष ने यह भी अवगत कराया कि विवेचना के दौरान पीड़िता ने अभियोजन के आरोपों का समर्थन नहीं किया तथा अपने बयान में लगाए गए आरोपों को स्वीकार नहीं किया।

जिला जेल में अफसरों का औचक छापा, बैरकों से अस्पताल तक खंगाली व्यवस्थाएं

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। जिला कारागार में मंगलवार को उस समय हलचल बढ़ गई, जब जिला जज सुनील कुमार, जिलाधिकारी इन्द्रजीत सिंह और पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने जेल का औचक निरीक्षण किया। अधिकारियों ने जेल परिसर, बैरकों और अस्पताल का सघन निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान महिला एवं पुरुष बंदियों की बैरकों की गहन जांच की गई। अधिकारियों ने जेल मेस में भोजन की गुणवत्ता, साफ-सफाई और अस्पताल में भर्ती बंदियों के उपचार की स्थिति का भी निरीक्षण किया। व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने बंदियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही मुलाकात करने आने वाले लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए गए। निरीक्षण के दौरान जेल प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ रखने तथा बंदियों की सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। औचक निरीक्षण से जेल प्रशासन में पूरे दिन सतर्कता का माहौल बना रहा।

'मेहनत का मिला पूरा हक: मुख्यमंत्री योगी

सीएम योगी ने 930 अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र; युवाओं ने कहा- भ्रष्टाचारमुक्त रही भर्ती

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया अब सिफारिश और पैरवी के दाग से पूरी तरह मुक्त हो चुकी है। बुधवार को इसकी एक और शानदार बानगी देखने को मिली, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा चयनित 930 कंप्यूटर ऑपरेटरों (ग्रेड-ए) को नियुक्ति पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री के हाथों से नियुक्ति पत्र पाते ही युवाओं के चेहरे खुशी से चमक उठे। चयनित अभ्यर्थियों ने एक सुर में कहा कि पूरी भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और भ्रष्टाचारमुक्त रही है। उन्होंने माना कि आज यूपी में सिर्फ और सिर्फ मेहनत के दम पर सरकारी नौकरी हासिल की जा सकती है।

'न सिफारिश, न पैरवी... सिर्फ 400 रुपये में पक्की हुई नौकरी'

इस पूरी चयन प्रक्रिया में योगी सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' नीति का साफ असर दिखा। लखनऊ के रहने वाले चयनित अभ्यर्थी नीरज पाल ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि उन्हें चयन के लिए किसी भी तरह की सिफारिश या घूस की जरूरत नहीं पड़ी। उनका पूरा खर्च केवल 400 रुपये था, जो उन्होंने आवेदन शुल्क के रूप में जमा किया था। वहीं, जौनपुर निवासी अरविंद कुमार ने भी परिणाम की पारदर्शिता की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र मिलना उनके जीवन का सबसे गर्व का क्षण है।

बेटियों ने कहा- 'बिना भेदभाव के मिला मेहनत का हक'

इस भर्ती में चयनित बेटियों ने भी चयन प्रक्रिया पर पूरा भरोसा जताया। हरदोई की रहने वाली अनामिका राजवंशी ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि पूरी प्रक्रिया बिना किसी पक्षपात और भेदभाव के संपन्न हुई है। मेहनत करने वालों को उनका हक मिला है, जिससे युवाओं का सरकारी सिस्टम पर विश्वास और गहरा हुआ है। एक अन्य चयनित अभ्यर्थी अंशिका मिश्रा ने कहा कि यह नियुक्ति उनके पूरे परिवार के लिए बड़े गर्व की बात है और वह अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा व ईमानदारी के साथ निभाएंगी।

आधुनिक तकनीक से प्रदेश की सेवा का संकल्प

मुख्यमंत्री से नियुक्ति पत्र प्राप्त करने को कई अभ्यर्थियों ने अपने जीवन का सबसे यादगार पल बताया। बिजनौर के पर्व कुमार ने कहा कि शासन-प्रशासन ने जिस ईमानदारी और विश्वास के साथ भर्ती पूरी की है, उसी ईमानदारी से वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। इसी तरह, कार्तिक सैनी ने विश्वास दिलाया कि वे आधुनिक तकनीकों का भरपूर उपयोग करते हुए पुलिस विभाग की कार्यक्षमता बढ़ाने में अपना शत-प्रतिशत योगदान देंगे।

मोहर्रम-2026 को लेकर लखनऊ में हाई अलर्ट, 5 जोन और 18 सेक्टर में तैनात होगा भारी पुलिस बल

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। मोहर्रम-2026 के अवसर पर राजधानी लखनऊ में शांति, सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लखनऊ पुलिस ने व्यापक सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था लागू की है। ताजिया जुलूसों, मजलिसों और अन्य धार्मिक आयोजनों को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पूरे कमिश्नरेट क्षेत्र में बहुस्तरीय सुरक्षा योजना तैयार की गई है। संवेदनशील और अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती के साथ-साथ सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के माध्यम से चौबीसों घंटे निगरानी की जाएगी। पुलिस आयुक्त के निर्देशन में मोहर्रम के दौरान निकलने वाले जुलूसों और धार्मिक आयोजनों को ध्यान में रखते हुए विशेष सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। पश्चिमी जोन सहित कमिश्नरेट के विभिन्न क्षेत्रों को सुरक्षा व्यवस्था के लिए पांच जोन और 18 सेक्टर में विभाजित किया गया है। चौक, ठाकुरगंज, सआदतगंज, बाजारखाला, वजीरगंज, अमीनाबाद सहित अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। इन इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल, पीएसी और वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती की गई है।मोहर्रम ड्यूटी के लिए चार पुलिस उपायुक्त, 19 अपर पुलिस उपायुक्त और 52 सहायक पुलिस आयुक्त स्तर के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनके अलावा 91 निरीक्षक, 1104 उपनिरीक्षक तथा 2477 मुख्य आरक्षी एवं आरक्षी सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। सुरक्षा प्रबंधों को और मजबूत बनाने के लिए 14 कंपनियां तथा दो प्लाटून पीएसी की भी तैनाती की गई है।महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को विशेष प्राथमिकता देते हुए महिला पुलिसकर्मियों, एंटी रोमियो स्क्वॉड, पिंक पेट्रोल और डायल-112 की टीमों को भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में लगातार भ्रमणशील रहने के निर्देश दिए गए हैं। ये टीमें सार्वजनिक स्थलों पर निगरानी रखते हुए किसी भी अप्रिय घटना की रोकथाम करेंगी।पुलिस ने मोहर्रम के दौरान निकलने वाले ताजिया, अलम और मातमी जुलूसों के पारंपरिक मार्गों का सत्यापन कर लिया है। प्रत्येक प्रमुख जुलूस मार्ग पर पुलिस पिकेट, मोबाइल गश्त और विशेष निगरानी की व्यवस्था की गई है। भीड़ नियंत्रण के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा तथा संवेदनशील स्थलों पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। जुलूसों के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इसके लिए आयोजन समितियों और धर्मगुरुओं के साथ लगातार समन्वय स्थापित किया जा रहा है।लखनऊ पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को तकनीकी रूप से भी सुदृढ़ बनाया है। शहर के प्रमुख स्थलों, जुलूस मार्गों, इमामबाड़ों और कर्बला स्थलों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी की जाएगी।

यूपी के बेसिक विद्यालयों में अब 24 जून तक रहेगा ग्रीष्मकालीन अवकाश, 25 जून से शुरू होगा पठन-पाठन

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने भीषण गर्मी और हीट वेव की परिस्थितियों को देखते हुए बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित तथा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब प्रदेश के परिषदीय और मान्यता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रत्येक वर्ष 20 मई से 24 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा तथा 25 जून से नियमित पठन-पाठन शुरू होगा।इस संबंध में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा द्वारा आदेश जारी कर निदेशक बेसिक शिक्षा तथा सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि परंपरागत रूप से बेसिक शिक्षा परिषद के शैक्षणिक कैलेंडर में 20 मई से 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया जाता रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी और हीट वेव के कारण जिलाधिकारियों द्वारा स्थानीय स्तर पर विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की उपस्थिति को अतिरिक्त अवधि तक स्थगित करना पड़ता था।इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए शासन स्तर पर विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2026 से ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि बढ़ाकर 24 जून तक कर दी जाए। इसके तहत छात्र-छात्राओं के लिए 20 मई से 24 जून तक अवकाश रहेगा, जबकि 25 जून से विद्यालयों में नियमित शिक्षण कार्य प्रारंभ होगा।शासन ने विद्यालयों के संचालन को सुचारु बनाने के लिए शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की जिम्मेदारियां भी निर्धारित की हैं। आदेश के अनुसार 22, 23 और 24 जून को सभी शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी विद्यालयों में उपस्थित रहेंगे और नए शैक्षणिक सत्र की तैयारियां पूरी करेंगे। इस दौरान लेसन प्लान तैयार करना, मध्याह्न भोजन व्यवस्था सुनिश्चित करना, पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता की समीक्षा, विद्यालय प्रबंधन समिति के साथ बैठक, समुदाय की सहभागिता बढ़ाने के प्रयास, बाल वाटिका की तैयारी, विद्यालय परिसर, रसोईघर एवं शौचालयों की साफ-सफाई सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएंगी।इसके अलावा विद्यालयों में खेल सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने, स्मार्ट क्लास एवं आईसीटी लैब को क्रियाशील रखने, विद्युत आपूर्ति चालू रखने तथा पेयजल और शौचालयों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि 25 जून को विद्यालय खुलते ही छात्र-छात्राओं का नियमित पठन-पाठन बिना किसी बाधा के प्रारंभ हो सके।

12 वर्ष विश्वास, विकास और जनकल्याण के नाम : कानपुर में विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ, केशव प्रसाद मौर्य ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित '12 वर्ष विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के' विषयक विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ मंगलवार को कानपुर नगर स्थित बृजेन्द्र स्वरूप पार्क में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए प्रदर्शनी स्टॉलों का अवलोकन कर केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास परियोजनाओं तथा उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त की।उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्षों और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार के 9 वर्षों के दौरान सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भर भारत और आधारभूत संरचना के

विकास के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शनी सरकार की विकास यात्रा को जन-जन तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम है।उन्होंने कहा कि विकसित भारत-2047 का संकल्प केवल सरकार का लक्ष्य नहीं है, बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक की सहभागिता से पूरा होने वाला राष्ट्रीय अभियान है। ऐसे आयोजन जनता को विकास योजनाओं से जोड़ने और उन्हें राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सहभागी बनाने का कार्य करते हैं। उन्होंने लोगों से अधिक से अधिक संख्या में प्रदर्शनी का अवलोकन कर विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने और उनका लाभ उठाने की अपील की।प्रदर्शनी के दौरान उप मुख्यमंत्री ने महिला एवं बाल विकास विभाग के स्टॉल पर आयोजित विभिन्न संस्कार कार्यक्रमों में भी सहभागिता की। उन्होंने त्रिशा और आरव का विद्यारंभ संस्कार कराया, जबकि दर्श और आरोही का अन्नप्राशन संस्कार संपन्न कराया। साथ ही करिश्मा, लक्ष्मी और पूजा सिंह की गोदभराई कर उन्हें शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि स्वस्थ, शिक्षित और सशक्त मातृशक्ति ही विकसित समाज की मजबूत नींव होती है।

केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार की सभी योजनाओं का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना है। रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, आधारभूत सुविधाओं और कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आम नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है।प्रदर्शनी में कानपुर नगर के विकास की झलक भी देखने को मिल रही है। नगर निगम, डूडा, ट्रूफ कंफर्ट्स लिमिटेड, नेयवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड, पनकी तापीय विस्तार परियोजना, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, बेसिक शिक्षा विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, एलिम्को, महिला कल्याण, समाज कल्याण, स्वास्थ्य विभाग, पराग डेयरी और मिशन शक्ति सहित अनेक विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए हैं।इसके अतिरिक्त कानपुर नगर की सभी दस विधानसभा क्षेत्रों में हुए विकास कार्यों और उपलब्धियों को भी प्रदर्शनी में आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। वहीं फूड कोर्ट आगंतुकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।पत्रकारों से बातचीत के दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियों, योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी आम जनता तक पहुंचाना इस प्रदर्शनी का प्रमुख उद्देश्य है।

गोमतीनगर पुलिस की बड़ी सफलता, चार दिन में सकुशल बरामद हुई नाबालिग, अपहरण का आरोपी गिरफ्तार

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। गोमतीनगर पुलिस ने नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले का त्वरित खुलासा करते हुए चार दिन के भीतर किशोरी को सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस ने मामले में नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस की इस कार्रवाई से परिजनों ने राहत की सांस ली है।पुलिस के अनुसार 14 जून 2026 को एक व्यक्ति ने थाना गोमतीनगर में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग पुत्री को एक युवक बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तत्काल मुकदमा संख्या 234/2026 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) और 87 के तहत मामला पंजीकृत किया। मामले की विवेचना

उपनिरीक्षक अशोक कुमार यादव को सौंपी गई।नाबालिग के लापता होने की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारियों ने उसकी शीघ्र बरामदगी के निर्देश दिए। इसके बाद पुलिस टीम ने संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी, तकनीकी साक्ष्यों का संकलन किया और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। पुलिस द्वारा लगातार की जा रही तलाश और निगरानी के दौरान महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे, जिसके आधार पर कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया।इसी क्रम में 17 जून 2026 को गोमतीनगर पुलिस की टीम क्षेत्र में तलाश और सुरागरसी में जुटी हुई थी। तभी मुखबिर से सूचना मिली कि मामले में वांछित आरोपी दयाल चौराहे के आसपास मौजूद है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान उसके साथ मौजूद नाबालिग किशोरी को भी सकुशल बरामद कर लिया गया।गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोहम्मद हन्जला पुत्र मोहम्मद नफीस निवासी समनान गार्डेन, बालागंज, थाना ठाकुरगंज, लखनऊ के रूप में हुई है। आरोपी की उम्र लगभग 21 वर्ष बताई गई है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है तथा मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की भी जांच की जा रही है।पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बरामद किशोरी का आवश्यक चिकित्सीय परीक्षण और बयान दर्ज कराने सहित सभी वैधानिक प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। वहीं आरोपी के विरुद्ध दर्ज मुकदमे में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।इस अभियान को सफल बनाने में उपनिरीक्षक अशोक कुमार यादव, कांस्टेबल पंकज कुमार तथा महिला कांस्टेबल टीना रानी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

पुलिस अधिकारियों ने टीम की सराहना करते हुए कहा कि महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों के प्रति लखनऊ पुलिस पूरी संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ कार्य कर रही है

लखनऊ को जलभराव मुक्त बनाने की दिशा में तेज़ी, ए.के. शर्मा ने विकास परियोजनाओं और नालों का किया स्थलीय निरीक्षण

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बुधवार को राजधानी लखनऊ में विभिन्न विकास परियोजनाओं तथा जलनिकासी से संबंधित कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार नागरिकों को बेहतर शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा शहरों को स्वच्छ, सुरक्षित और जलभराव मुक्त बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है।निरीक्षण की शुरुआत अयोध्या रोड एवं कुकरैल नदी के किनारे अतिक्रमण मुक्त कराई गई भूमि पर उपवन योजना के अंतर्गत विकसित किए जा रहे 'शक्तिवन' परियोजना से हुई। मंत्री ने परियोजना की प्रगति का जायजा लिया और कार्यों पर संतोष व्यक्त किया।

₹7.50 लाख से अधिक चिकित्सा दावों की जांच के लिए समिति गठित, कैशलेस उपचार पर होगी कड़ी निगरानी

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीटीसीएल) ने पावर कॉरपोरेशन, सहयोगी वितरण कंपनियों, ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन तथा राज्य विद्युत उत्पादन निगम के कार्यरत कर्मचारियों, पेंशनरों एवं उनके पात्र आश्रितों को उपलब्ध कराई जा रही कैशलेस चिकित्सा सुविधा में पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। यह समिति सूचीबद्ध चिकित्सालयों द्वारा प्रस्तुत ₹7.50 लाख से अधिक के चिकित्सा दावों की जांच करेगी तथा गैर सूचीबद्ध उपचारों की अनुमन्यता एवं दरों का निर्धारण भी करेगी।11 जून 2026 को जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार निगम द्वारा मान्यता प्राप्त सूचीबद्ध अस्पतालों में कर्मचारियों एवं पेंशनरों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। बढ़ते चिकित्सा व्यय और उच्च राशि वाले दावों के परीक्षण की आवश्यकता को देखते हुए यह समिति गठित की गई है, जो उपचार की आवश्यकता, चिकित्सा व्यय की ग्राह्यता, निगमादेशों के अनुपालन तथा अस्पतालों द्वारा प्रस्तुत दावों की युक्तिसंगतता का परीक्षण करेगी।समिति के अध्यक्ष के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम के महाप्रबंधक (चिकित्सा) को नामित किया गया है। इसके अलावा संयुक्त सचिव प्रथम, अधीक्षण अभियंता (एचआर-03), वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, वरिष्ठ लेखाधिकारी तथा मेडिकल सेल के अधिशासी अभियंता को समिति में सदस्य बनाया गया है। मेडिकल सेल के अधिशासी अभियंता समिति के सदस्य-संयोजक होंगे।समिति को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह ₹7.50 लाख से अधिक के सभी कैशलेस चिकित्सा दावों और बिलों का परीक्षण करे। साथ ही उपचार की आवश्यकता, अपनाई गई चिकित्सा प्रक्रिया की उपयुक्तता तथा व्यय की ग्राह्यता की समीक्षा करेगी। समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि सभी दावे निगमादेशों और लागू नियमों के अनुरूप हों।आवश्यकता पड़ने पर समिति संबंधित चिकित्सालयों अथवा लाभार्थियों से स्पष्टीकरण एवं अतिरिक्त अभिलेख भी प्राप्त कर सकेगी। परीक्षण के बाद देय अथवा ग्राह्य राशि के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को अपनी संस्तुति उपलब्ध कराएगी। यदि किसी दावे में अनियमितता, अतिरिक्त भुगतान अथवा अग्राह्य व्यय पाया जाता है तो समिति अपना स्पष्ट अभिमत भी दर्ज करेगी।कार्यालय ज्ञापन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि गैर सूचीबद्ध उपचारों की अनुमन्यता और उनकी दरों का निर्धारण भी यही समिति करेगी।

उत्तर प्रदेश में पहली बार 'यू.पी. स्मॉल लाइवस्टॉक कॉन्क्लेव-2026' का शुभारम्भ

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में लघु पशुपालन क्षेत्र को वैज्ञानिक, संगठित और लाभकारी व्यवसाय के रूप में विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पहली बार आयोजित दो दिवसीय 'यू.पी. स्मॉल लाइवस्टॉक कॉन्क्लेव-2026' का शुभारम्भ बुधवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुआ। प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह तथा राज्यमंत्री कृष्णा पासवान ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कॉन्क्लेव का उद्देश्य भेड़, बकरी एवं सूकर पालन को आधुनिक तकनीकों से जोड़ते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार को नई गति प्रदान करना है।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पशुधन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। गोवंश संरक्षण के साथ-साथ लघु पशुधन क्षेत्र को भी विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि यह कॉन्क्लेव लघु पशुपालन को रोजगार, पोषण सुरक्षा और ग्रामीण समृद्धि के मजबूत आधार के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।उन्होंने उद्यमियों से इस क्षेत्र में निवेश का आह्वान करते हुए कहा कि प्रदेश में सुदृढ़ कानून व्यवस्था, बेहतर संपर्क व्यवस्था और निवेश अनुकूल वातावरण के कारण वर्तमान समय पूंजी निवेश के लिए अत्यंत उपयुक्त है। उन्होंने कहा कि कॉन्क्लेव लघु पशुधन क्षेत्र से जुड़े वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, उद्यमियों, निवेशकों और पशुपालकों को एक साझा मंच उपलब्ध कराएगा, जहां तकनीक, अनुसंधान, मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण, विपणन और उद्यमिता विकास जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा होगी।मंत्री ने बताया कि 20वीं पशुगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक पशुधन संपन्न राज्य है। प्रदेश में लगभग 144.80 लाख बकरियां, 9.85 लाख भेड़ें तथा 4.09 लाख सूकर हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और किसानों की अतिरिक्त आय बढ़ाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है।उन्होंने विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि बकरी पालन योजना के तहत 60 हजार रुपये लागत की इकाई पर 90 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। वर्ष 2025-26 में 1786 इकाइयां स्थापित की गईं, जबकि वर्ष 2026-27 में 1896 इकाइयों का लक्ष्य रखा गया है। इसी प्रकार भेड़ पालन योजना के तहत 1.70 लाख रुपये लागत वाली इकाइयों पर 90 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। वर्ष 2025-26 में 224 इकाइयां स्थापित की गईं तथा आगामी वर्ष के लिए 225 इकाइयों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

जन चौपाल में गूंजे पेयजल, सीवर और आवारा कुत्तों के मुद्दे, महापौर सुषमा खर्कवाल ने दिए त्वरित समाधान के निर्देश

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। केंद्र सरकार के 12 वर्ष तथा उत्तर प्रदेश सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर नगर निगम लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे जन चौपाल अभियान के तहत बुधवार को जोन-4 के गोमती नगर वार्ड स्थित मारुति पुरम पार्क में जन चौपाल का आयोजन किया गया। महापौर सुषमा खर्कवाल की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने भाग लेकर अपनी समस्याएं, सुझाव और क्षेत्रीय विकास से जुड़े मुद्दे सीधे प्रशासन के समक्ष रखे जन चौपाल में नागरिकों ने सबसे प्रमुख रूप से पेयजल आपूर्ति की समस्या को उठाया। मारुति पुरम एवं आसपास के क्षेत्रों के निवासियों ने बताया कि लंबे समय से पानी की अनियमित आपूर्ति के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में पर्याप्त मात्रा में

पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिससे दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। नागरिकों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए महापौर ने जलकल विभाग के अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई कर समस्या के स्थायी समाधान के निर्देश दिए।कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रवासियों ने एचएएल नाले की जर्जर स्थिति का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। नागरिकों ने बताया कि नाले के क्षतिग्रस्त होने के कारण जल निकासी प्रभावित हो रही है और बरसात के मौसम में स्थिति और गंभीर हो सकती है। इस पर महापौर सुषमा खर्कवाल ने जानकारी दी कि नाले की मरम्मत एवं सुधार कार्य के लिए बजट स्वीकृत हो चुका है तथा शीघ्र ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्य में तेजी लाकर क्षेत्रवासियों को जल्द राहत प्रदान की जाए।जन चौपाल में सीवर व्यवस्था को लेकर भी लोगों ने नाराजगी व्यक्त की। नागरिकों ने बताया कि कई स्थानों पर सीवर लाइनें क्षतिग्रस्त हैं और नियमित सफाई न होने के कारण गंदगी एवं दुर्गंध की समस्या बनी रहती है। इससे लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। महापौर ने संबंधित अधिकारियों को सीवर नेटवर्क की विस्तृत जांच कर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।क्षेत्र में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या और डॉग बाइट की घटनाओं को लेकर भी नागरिकों ने चिंता व्यक्त की। स्थानीय लोगों ने बताया कि बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों में भय का माहौल बना हुआ है तथा कई बार कुत्तों के हमले की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इस पर महापौर ने नगर निगम के संबंधित अधिकारियों को प्रभावी अभियान चलाकर समस्या के समाधान तथा नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।जन चौपाल में महापौर ने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं को सीधे सुनना और उनका स्थानीय स्तर पर त्वरित एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जन चौपाल में प्राप्त सभी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए तथा प्रत्येक प्रकरण की नियमित समीक्षा की जाए।उन्होंने कहा कि नगर निगम लखनऊ शहर को बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने, आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने और जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। जन चौपाल अभियान प्रशासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित कर समस्याओं के समाधान का प्रभावी माध्यम बन रहा है।

अमेरिका व ईरान के बीच बने समझौते मसौदे के वैश्विक मायने

अमेरिका और ईरान के बीच हाल में उभरे समझौता-ढांचे (Framework Agreement) को यदि अंतिम रूप मिल जाता है, तो इसके प्रभाव केवल दोनों देशों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया, वैश्विक ऊर्जा बाजार और विश्व राजनीति पर पड़ेंगे। समझौते में युद्धविराम, परमाणु कार्यक्रम पर नियंत्रण, तेल प्रतिबंधों में राहत, ईरान की जमी हुई संपत्तियों की रिहाई तथा होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने जैसे मुद्दे शामिल बताए जा रहे हैं। यदि यह समझौता सफलतापूर्वक लागू होता है, तो इसे 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक घटनाक्रमों में गिना जा सकता है। आइए इसके वैश्विक मायने को क्रमशः समझते हैं:-

पहला, वैश्विक ऊर्जा बाजार को मिलेगी बड़ी राहतः होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के तेल और LNG व्यापार का एक अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग है। इस मार्ग पर रणनीति पूर्वक ईरान ने अपना मजबूत कब्जा जमा लिया है। लिहाजा, इसके खुलने और तनाव घटने से कच्चे तेल की आपूर्ति सामान्य हो सकती है, जिससे तेल की कीमतों पर दबाव कम होगा। समझौते की खबर आते ही वैश्विक बाजारों में तेल कीमतों में गिरावट और शेयर बाजारों में तेजी देखी गई।

दूसरा, पश्चिम एशिया में घटेगा युद्ध का खतराः यदि अमेरिका-ईरान टकराव कम होता है, तो लेबनान, इराक, सीरिया और खाड़ी क्षेत्र में भी तनाव कम होने की संभावना बढ़ेगी। समझौते के तहत क्षेत्रीय संघर्षों को शांत करने की बात भी सामने आई है। इससे भारत को लाभ यह होगा कि यूरोप, अरब देशों, मध्य एशिया के देशों और रूस के साथ विकसित होने वाले महत्वपूर्ण व्यापारिक परिवहन कॉरिडोर के काम में गति आएगी।

तीसरा, परमाणु प्रसार पर नियंत्रणः ईरान द्वारा परमाणु हथियार न बनाने, यूरेनियम संवर्धन को सीमित करने तथा परमाणु गतिविधियों पर नियंत्रण की दिशा में सहमति अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इससे मध्य पूर्व में परमाणु हथियारों की दौड़ पर कुछ हद तक रोक लग सकती है। साथ ही, पाकिस्तान पर भी परमाणु हथियार हटाने का दबाव बढ़ेगा।

चौथा, चीन और रूस की रणनीति पर असरः पिछले वर्षों में ईरान, चीन और रूस के बीच रणनीतिक निकटता बढ़ी थी। इससे भारत की भी परेशानी बढ़ रही थी, क्योंकि ईरान-पाकिस्तान-अफगानिस्तान के आतंकवादी कॉरिडोर को नियंत्रित करने में अमेरिका-चीन के षड्यंत्रकारी बाधक बन रहे थे। रूस भी मजबूरी में ईरान को साथ दे रहा है। ऐसे में यदि अमेरिका-ईरान संबंध सुधरते हैं, तो तेहरान को पश्चिमी निवेश और बाजारों तक पहुंच मिल सकती है, जिससे उसकी चीन और रूस के अलावा पाकिस्तान पर रणनीतिक निर्भरता कुछ कम हो सकती है। यह वैश्विक शक्ति-संतुलन में महत्वपूर्ण बदलाव होगा।

पांचवां, भारत के लिए क्या मायने?: भारत के लिए यह समझौता कई कारणों से सकारात्मक हो सकता हैः- एक,

तेल आयात व अन्य सामान के सस्ता होने की संभावना बढ़ेगी। खाड़ी क्षेत्र में भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा बेहतर होगी। चाबहार बंदरगाह और भारत-ईरान व्यापार को नई गति मिल सकती है। पश्चिम एशिया में स्थिरता भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगी। यहां चीनी हस्तक्षेप कम होने से भारत पश्चिमी मोर्चे पर मजबूत होगा।

छठा, लेकिन चुनौतियां अभी बाकी हैंः चूंकि समझौते पर अभी भी पूर्ण सहमति नहीं बनी है, क्योंकि चीन-रूस दिल से ऐसा नहीं चाहते। लिहाजा, ईरान के कट्टरपंथी गुट इसका विरोध कर रहे हैं और इजराइल-हिज्बुल्लाह मोर्चे पर तनाव भी बना हुआ है। चूंकि कट्टरपंथियों ने बलिदान देकर ईरान को इतना मजबूत बनाया है। इसलिए उनके खिलाफ कोई भी ईरानी सरकार नहीं जा सकती। यही वजह है कि कई रिपोर्टों में कहा गया है कि अंतिम हस्ताक्षर और कार्यान्वयन अभी अनिश्चित हैं।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि यदि यह समझौता सफलतापूर्वक लागू होता है, तो इसे 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक घटनाक्रमों में गिना जा सकता है। इससे तेल बाजार स्थिर होंगे, परमाणु संकट टलेगा, पश्चिम एशिया में शांति की संभावना बढ़ेगी और भारत सहित अनेक देशों को आर्थिक लाभ मिलेगा। लेकिन इसकी स्थिरता इस बात पर निर्भर करेगी कि अमेरिका, ईरान, इजराइल और क्षेत्रीय शक्तियां अपने-अपने वादों का कितना पालन करती हैं। मेरी राय में यह समझौता जितनी जल्दी हो जाए, भारतीय हित उतनी जल्दी ही सधने शुरू जाएंगे।

रिकॉर्ड के मोर्चे पर कौन भारी, कौन कमजोर

उमेश चतुर्वेदी

प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जिस तरह का राजनीतिक माहौल स्थापित हो चुका है, उसमे अगर प्रगतिशील खेमा और कांग्रेस की आलोचना के केंद्र में मोदी ना रहें तो ही हैरत होगी।

इस बार 11 जून की तारीख भारतीय इतिहास के लिए विशेष बनकर आई। इसी दिन निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा दिन शासन चलाने का रिकॉर्ड कायम कर दिया। इसके पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे ज्यादा 4398 दिन प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू के नाम है। मौजूदा दौर विशेषकर विजुअल मीडिया के वर्चस्व का दौर है। विजुअल मीडिया की चूंकि उत्सवधर्मिता केंद्रित है, लिहाजा इस रिकॉर्ड को लेकर सत्ता पक्ष में उत्साह का माहौल होना ही था और ऐसा है भी। लेकिन इसे लेकर आलोचनाओं की बाढ़ भी आ गई है। विशेषकर प्रगतिशील खेमे से मोदी के इस रिकॉर्ड को लेकर तंज में आलोचनाएं की जा रही हैं। इन आलोचनाओं का भाव कुछ वैसे ही है, जैसे कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली। आलोचकों की नजर में कहावत के राजा भोज नेहरू हैं और गंगू मोदी।

प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ अरसा पहले संसद को संबोधित करते हुए देश के विकास में अतीत के हर प्रधानमंत्री के योगदान को याद किया था। इतिहास क्रम में हर प्रधानमंत्री ने कुछ न कुछ योगदान दिया ही है। हर प्रधानमंत्री की युगीन आवश्यकताएं और परिस्थितियां अलग रही हैं।

इसलिए अव्वल तो ऐसी तुलनाएं होनी ही नहीं चाहिए थी। क्योंकि नेहरू के युग में भारत की जो स्थिति थी, वह अब नहीं है। इतिहास का कोई खंड कठिन होता है तो कोई आसान। इसलिए इतिहास के काल खंड की बुनियाद पर उस दौर के शासक की परख होनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि भविष्य का शासक अपनी उपलब्धियों का जश्न नहीं मना सकता।

प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जिस तरह का राजनीतिक माहौल स्थापित हो चुका है, उसमे अगर प्रगतिशील खेमा और कांग्रेस की आलोचना के केंद्र में मोदी ना रहें तो ही हैरत होगी। प्रगतिशील खेमा मोदी को कमतर दिखाने की कोशिश में नेहरू को सबसे ज्यादा दिनों तक प्रधानमंत्री दिखाने की कोशिश कर रहा है। इस आलोक में इतिहास के तथ्यों को जांचना जरूरी है। इसमें दो राय नहीं कि जब 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी मिली, तब पंडित जवाहर लाल नेहरू ने ही देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। लेकिन वह किसी एक दल विशेष यानी कांग्रेस की ही सरकार नहीं थी, बल्कि एक तरह से वह राष्ट्रीय सरकार थी, जिसमें अंबेडकर भी थे और श्यामाप्रसाद मुखर्जी भी।

द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ऐसा लगने लगा था कि भारत को आजादी मिल जाएगी। इस बीच ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी और लॉर्ड एटली प्रधानमंत्री बने। एटली ने चुनावी वादा किया था कि अगर उनकी पार्टी की सरकार बनी तो भारत को स्वाधीनता दी जाएगी। जब उन्होंने ब्रिटेन की कमान संभाल ली तो उन्होंने भारत को आजादी देने की प्रक्रिया तेज कर दी। इसी सिलसिले में 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। मिशन के सामने सवाल यह था कि सत्ता का हस्तांतरण किसे किया जाएगा, क्योंकि उन दिनों भारत में दो बड़े और प्रमुख दल थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। लेकिन सत्ता किसे सौंपी जाए, इस सवाल के साथ ही भारत की भावी सरकार और विधान को तैयार करने के लिए संविधान सभा का चुनाव 1946 में हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस को 208 और मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिलीं। दूसरे दलों और निर्दलीयों को 15 सीटें मिलीं थी। इसके पहले प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस को 923 और मुस्लिम लीग को 425 सीटें मिली थीं। कांग्रेस को सामान्य सीटों के नब्बे प्रतिशत हिस्से पर जीत मिली, मुस्लिम बहुल 87 प्रतिशत सीटों पर मुस्लिम लीग को जीत मिली। इसके बाद सबसे बड़ा दल होने के नाते कांग्रेस को ही सत्ता हस्तांतरण होना तय हुआ। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष का महत्व बढ़ गया। उन दिनों कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए अधिकांश प्रांतीय समितियों ने सरदार पटेल का नाम आगे किया था, जबकि कुछ ही प्रांतीय कांग्रेस समितियों ने जवाहर लाल नेहरू का नाम आगे किया। चूंकि गांधी जी पहले ही कह चुके थे कि उनके बाद जवाहर उनकी भाषा बोलेगा यानी सत्ता उन्हें मिलेगी, इसलिए वे ही अध्यक्ष बनाए गए। इसके बाद सत्ता हस्तांतरण प्रक्रिया के तहत 2 सितंबर 1946 को 'अंतरिम सरकार' का गठन हुआ, जिसमें नेहरू जी को 'वायसराय की कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष' बनाया गया, उस पद का नाम प्रधानमंत्री नहीं था। इसे अंतरिम सरकार कहा गया। भले ही कुछ लोग सुविधा के लिए नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल को उसी दिन से मान लेते हैं। यहां याद करना जरूरी है कि वायसराय की कार्यकारी परिषद के पदेन अध्यक्ष खुद वायसराय लॉर्ड वेवेल थे। उनके बाद आए वायसराय माउंटबेटन इसके अध्यक्ष रहे।

देश को स15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947' के तहत देश को आजाद घोषित किया गया। इस कानून के मूल पाठ में कहीं भी ₹प्राइम मिनिस्टर₹ या प्रधानमंत्री शब्द नहीं लिखा हुआ है। हालांकि पंद्रह अगस्त 1947 की आधी रात को नेहरू ने स्वाधीन सरकार के मंत्री के रूप में शपथ ली, भले ही वे उसके मुखिया थे। नेहरू ने अंग्रेजी में शपथ लेते हुए 'ऑफिस ऑफ मिनिस्टर' यानी मंत्री पद की शपथ ली थी, प्रधानमंत्री पद की नहीं। इसके बाद ही उन्होंने 'नियति से साक्षात्कार' वाला प्रसिद्ध भाषण दिया था। यहां याद करना चाहिए कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत तत्कालीन गवर्नर-जनरल को ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में दोनों उपनिवेशों भारत और पाकिस्तान का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया था। जिन्हें सलाह देने और शासन चलाने के लिए एक मंत्रि परिषद का प्रावधान था। इस प्रावधान में प्रधानमंत्री या प्रीमियर या प्राइम मिनिस्टर का कोई पद नहीं है। गवर्नर-जनरल को इसी मंत्रि परिषद की सलाह पर शासन चलाना था।

मोदी को सबसे लंबे समय तक बतौर निर्वाचित प्रधानंत्री काम करने के रिकॉर्ड को गलत साबित करने वाला प्रगतिशील तबके का तर्क है कि 1946 के चुनावों में कांग्रेस सबसे बड़ा दल बन कर उभरी और उसके निर्वाचित नेता के तौर पर नेहरू ने सरकार चलाई। लेकिन हकीकत यह है कि 1946 का चुनाव वयस्क मतदान के अधिकार और एक व्यक्ति, एक वोट के सिद्धांत के तहत नहीं हुआ था। तब वोटर होने की शर्त संपत्ति, शिक्षा, कर भुगतान आदि था। मुसलमान सिर्फ मुस्लिम बहुल सीटों के ही मतदाता थे। एक तरह से यह सार्वभौम वयस्क मतदान के अधिकार से रहित चुनाव था। इसलिए सही मायने में 1946 का चुनाव ना तो समानता और वयस्क मतदान के अधिकार से लैस था, न ही पूरे देश के मतदाताओं का प्रतिबिंब था। एक तरह से कहें तो यह सिर्फ दस प्रतिशत लोगों के मतदान की बुनियाद पर हुआ चुनाव था। जिसमें हर वयस्क की भागीदारी नहीं थी। उन दिनों धार्मिक आधार पर अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्र भी थे। इसलिए 1946 का चुनाव सही मायने में संतुलित मतदान नहीं था। स्वाधीन भारत में पहला आम चुनाव 1951 -52 के बीच हुआ। जिसमें कांग्रेस को 364 सीटें मिलीं। इसी नतीजे के आधार पर पंडित नेहरू ने 13 मई 1952 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और 27 मई 1964 को मृत्यु पर्यंत अपने पद पर रहे। इसी लिहाज से नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन ही होता। आधुनिक सार्वभौम मतदान के अधिकार और सिद्धांत के लिहाज से देखें तो पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर असल कार्यकाल 13 मई 1952 से 27 मई 1964 तक का ही होता है।

टिप्पणी

सीजेरियन डिलीवरी

भारत में बीमा कवरेज बढ़ा है, जिसमें एक बड़ा हिस्सा सरकारी बीमा योजनाओं का है। संभवतः इसी कारण अस्पताल दंपत्तियों को अनिवार्य ना होने की स्थिति में भी सीजेरियन डिलीवरी पर राजी कर लेते हैं।

भारत में अब 90 फीसदी बच्चों का जन्म अस्पताल में होता है। ये अच्छी खबर नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे-6 (एनएफएचएस-6) रिपोर्ट से आई है। उधर नई सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैस्टिकल रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में कुल जितने बच्चों का जन्म हुआ, उनमें 66.4 प्रतिशत अपने माता-पिता की पहली संतान थे। लगभग 23 प्रतिशत दूसरी और 7.3 फीसदी तीसरी संतानों का जन्म हुआ। सिर्फ 3.5 प्रतिशत मामलों में चौथी या उसके बाद की संतानों का जन्म हुआ। ये आंकड़े स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन के लिए बढ़ी चेतना की तस्दीक करते हैं। एनएफएचएस-6 के मुताबिक भारत में टोटल फर्टिलिटी रेट (टीएफआर) 2.0 रह गया है, जो आदर्श 2.1 से थोड़ा कम है।

फिलहाल, यह चिंता का विषय नहीं है, लेकिन टीएफआर और गिरा, तो भविष्य में एक नई चुनौती देश के सामने आ सकती है। बहरहाल, एनएफएचएस-6 से अभी गंभीर चिंता का कारण बन चुका एक रुझान सामने आया है। इसके मुताबिक 2023-24 में प्राइवेट अस्पतालों में 54 प्रतिशत डिलीवरी सीजेरियन हुई। पश्चिम बंगाल में तो ये संख्या 87.7 और तेलंगाना 84 प्रतिशत थी। उल्लेखनीय है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन सिर्फ 10 से 15 प्रतिशत मामलों में सीजेरियन डिलिवरी को स्वीकार्य सीमा में मानता है। अमेरिका में स्वास्थ्य सेवाओं के लगभग पूरी तरह बीमा आधारित होने के बावजूद सीजेरियन डिलीवरी की दर 32 प्रतिशत ही है। स्कैंडेनेवियन देशों में तो यह 16 से 19 फीसदी तक है।

ये आंकड़े बताते हैं कि सीजेरियन डिलीवरी की जरूरत बहुत कम मामलों में पड़ती है। फिर भी भारत में प्राइवेट अस्पतालों में आधी से ज्यादा डिलीवरी इस तरीके से हो रही है, तो इसके पीछे मुख्य कारण मुनाफा कमाने की व्यापारिक मानसिकता को ही समझा जाएगा। एनएफएचएस-6 से सामने आया है कि भारत में बीमा कवरेज बढ़ा है, जिसमें बड़ा योगदान सरकारी बीमा योजनाओं का है। संभवतः इसी कारण अस्पताल दंपत्तियों को अनिवार्य ना होने की स्थिति में भी सीजेरियन डिलीवरी पर राजी कर लेते हैं। अगर ऐसा हो रहा है, तो इसकी पड़ताल की जरूरत है, क्योंकि सरकारी बीमा के तहत अस्पतालों को जो भुगतान होता है, वह करदाताओं की जेब से ही आता है।

ब्लॉग

स्वस्थ भारत, सशक्त भारत-स्वास्थ्य देखभाल विकास के 12 वर्ष

श्रीमती अनुप्रिया पटेल

बेहतर स्वास्थ्य प्रणाली से आर्थिक उत्पादकता बढ़ती है, कार्यबल की संख्या में बढ़ोतरी होती है और विकास दीर्घावधि तक होता है। इसलिए, अच्छी सेहत न केवल समाज के लिए अच्छा संकेत है, बल्कि यह देश की एक संपत्ति भी है। यह वह आधार है, जिस पर मानवीय क्षमता का निर्माण होता है और देश की ताकत मापी जाती है। इसलिए, बेहतर सेहत न केवल समाज के लिए अच्छा है, बल्कि यह देश की एक संपत्ति है और इसमें लगाया गया हर रुपया देश के लोगों में किया गया निवेश है।

इस तरह, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) , यानी यह सुनिश्चित करना कि सभी लोग, चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, बिना किसी आर्थिक परेशानी के, जब और जहाँ ज़रूरत हो, अच्छी गुणवत्ता की सभी ज़रूरी स्वास्थ्य सेवाएं हासिल कर सकें। यह न केवल 2030 तक हासिल किया जाने वाला सतत विकास का लक्ष्य है, बल्कि सेहत से जुड़ी एक प्राथमिकता भी है। भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 (एनएचपी 2017), सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) और एसडीजी 3 को हासिल करने के लक्ष्य के अनुरूप है और यह एक सरल लेकिन मज़बूत सोच पर आधारित है -स्वास्थ्य सेवाओं तक हर व्यक्ति की पहुँच होनी चाहिए। इसके चार स्तंभ, किफायती होना, पहुँच, गुणवत्ता और उपलब्धता , उस सोच को वास्तिवकता में बदलते हैं और जीवन के सभी चरणों में देखभाल की एक व्यापक व्यवस्था को मज़बूत करते हैं। लक्ष्यों के अनुरूप, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राज्यों को स्वास्थ्य प्रणाली का एक एकीकृत तीन-स्तरीय मॉडल प्रदान करने में मदद करता है, जिसमें ग्रामीण और शहरी इलाकों (कमज़ोर वर्गों सहित) के बीच दोतरफा रेफरल लिंक शामिल हैं।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) प्राथमिक स्तर पर बीमारी से बचाव, सेहत को बढ़ावा देने, इलाज, पुर्नवास और प्रशामक देखभाल जैसी व्यापक स्वास्थ्य सेवाएँ देते हैं। ईसंजीवनी टेलीमेडिसिन प्लेटफ़ॉर्म इन एएएम के ज़रिए समुदाय को विशेषज्ञों से जोड़कर विशेषज्ञों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। साथ ही, एक खास टेली-मानस प्लेटफ़ॉर्म भी है, जिसने अब तक कुल 38.93 लाख लोगों तक पहुँच बनाई है।

एएएम से जुड़े द्वितीय स्तर के केंद्र जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी)/प्रथम रेफरल इकाई (एफआरयू) और ज़िला अस्पताल (डीएच) होते हैं, जो विशेषज्ञ के समक्ष इलाज और अस्पताल में भर्ती होने की सुविधा के लिए रेफरल का पहला ज़रिया होते हैं। वहीं, मेडिकल कॉलेज जैसे तृतीयक संस्थान सबसे ऊपर होते हैं और ज़्यादा जटिल व सुपर-स्पेशलिस्ट सेवाओं की ज़रूरतें पूरी करते हैं। इस तीन-स्तरीय प्रणाली को सरकारी स्वास्थ्य बजट में बढ़ोतरी का समर्थन प्राप्त है। पिछले दशक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पर होने वाला खर्च 168त्न बढ़ गया है, जो स्वास्थ्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता मानने के सरकार के संकल्प को दर्शाता है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर का सफ़र व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के विस्तार और प्रतिक्रियात्मक कार्यवाही से समस्या होने से पहले ही ध्यान रखने वाली देखभाल की ओर ज़रूरी बदलाव को दिखाता है। व्यापक स्वास्थ्य पैकेजों की संख्या 6 से बढ़ाकर 12 करना, भारत की बदलती आबादी और बीमारियों के बदलते पैटर्न के हिसाब से उठाया गया एक ज़रूरी कदम है। बढ़ती उम्र की आबादी और गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के बढ़ते मामलों की दोहरी चुनौतियों का सामना करते हुए, इसके दायरे में गैर-संचारी रोग, मानसिक स्वास्थ्य, बुज़ुर्गों की देखभाल, आपातकालीन सेवाएँ, आँख, कान-नाक-गला (ईएनटी) और मुँह की सेहत के साथ-साथ योग और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाली गतिविधियाँ शामिल हैं। यह सब उस आबादी की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो भारत अब बन रहा है। मई 2026 तक, देश भर में 1.8 लाख से ज़्यादा एएएम काम कर रहे हैं, ताकि लोगों को उनके घर के पास स्वास्थ्य सेवाएँ मिल सकें। इस विस्तार का असर एएएम में 120 करोड़ से ज़्यादा ओपीडी परामर्श, 70 करोड़ से ज़्यादा ईसंजीवनी टेली-परामर्श और अच्छी सेहत व कल्याण को बढ़ावा देने वाले 46.1 करोड़ से ज़्यादा वेलनेस सत्रों में साफ़ दिखता है। प्राथमिक देखभाल स्तर पर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और आम कैंसर (जैसे ओरल, ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर) के लिए आबादी-आधारित स्क्रीनिंग 30 साल से ज़्यादा उम्र के सभी वयस्कों के लिए की जाती है, जिससे बीमारी का जल्दी पता लगाना एक सामान्य प्रक्रिया बन जाती है। यह जांच आयुष्मान आरोग्य मंदिर के तहत सेवा वितरण का एक अहम हिस्सा है, जो एनसीडी की रोकथाम को व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में शामिल करती है। एनसीडी सेवाओं का विस्तार बीमारी का जल्दी पता लगाने, रोकथाम, प्रबंधन और इलाज के लिए एक बहु स्तरीय प्रयास है। समर्पित एनसीडी क्लीनिक, डे-केयर कैंसर केंद्र , तृतीयक देखभाल कैंसर केंद्र और राज्य कैंसर संस्थान, उन्नत ऑन्कोलॉजी सेवाओं को विकेंद्रीकृत करते हैं और विशेषज्ञ देखभाल को मरीज़ के करीब लाते हैं।

साथ ही, बचाव से जुड़ी गतिविधियों के लिए होल-ऑफ-गवर्नमेंट दृष्टिकोण अपनाया जाता है। एफएसएसएआई स्वस्थ खान-पान की आदतों को बढ़ावा देता है, फिट इंडिया मूवमेंट शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है और आयुष मंत्रालय योग और कल्याण को आगे बढ़ाता है। लगातार चलने वाले जन-जागरूकता अभियान और स्वास्थ्य दिवस मनाने जैसे कार्यक्रम इन प्रयासों को और मज़बूत करते हैं। खाने के तेल की खपत को 10त्न कम करने की प्रधानमंत्री मोदी की निजी अपील एक सरल लेकिन दमदार सोच को ज़ाहिर करती है कि एनसीडी के ख़िलाफ़ लड़ाई अस्पतालों के साथ-साथ घरों में भी जीती जाती है।

प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के विस्तार के लिए, एएएम स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य ऑफिसर्स का एक नया कैडर शुरू किया गया, जिससे क्लिनिकल और जन स्वास्थ्य से जुड़ी विशेषज्ञता समुदायों के और करीब आ गई। यह विस्तार लोगों के घर-द्वार तक भी पहुँचा, जहाँ फ्रंटलाइन नेटवर्क बढ़कर 10 लाख से ज़्यादा आशा (आशा) कार्यकर्ताओं तक पहुँच गया, जिन्होंने समुदाय को स्वास्थ्य प्रणाली से जोड़ा। विस्तार के साथ-साथ, भारत ने देखभाल के मापदंडों को बदलने की ज़्यादा मुश्किल चुनौती भी स्वीकार की। राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक, जो देश में ही विकसित और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणीकृत हैं, ने गुणवत्ता को सिफ़र् एक इच्छा से बदलकर एक जवाबदेही बना दिया। 65,000 से ज़्यादा जन स्वास्थ्य केंद्र, जिनमें 54,926 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शामिल हैं, अब एनक्यूएएस द्वारा प्रमाणीकृत हैं। इसके अलावा, आईपीएचएल के लिए लैब मानकों ने व्यवस्था में और मज़बूती और सटीकता लाई है।

एनक्यूएएस की सफलता का राज़ सिफ़र् मानदंड नहीं, बल्कि उसके आस-पास बनी व्यवस्था था, जैसे माँ और नवजात शिशु की देखभाल के लिए लक्ष्य, साफ़-सफ़ाई और संक्रमण नियंत्रण के लिए कायाकल्प और बच्चों की सेहत के लिए मुस्कान। इन सभी ने मिलकर गुणवत्ता को सिफ़र् एक मानक के बजाय एक आधारभूत स्तर बना दिया है। नतीजा यह है कि अब ऐसी व्यवस्था तैयार हुई है, जिसमें न सिफ़र् ज़्यादा लोगों का इलाज होता है, बल्कि बेहतर इलाज भी किया जाता है। अगर प्राथमिक देखभाल व्यवस्था का पहला वादा है, तो राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम जैसे खास कार्यक्रम देश भर में ओओपीई को कम करने के सरकार के संकल्प को और दिखाते हैं। इससे उन परिवारों की कुल मिलाकर 10,102 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बचत हुई है, जिन्हें वरना यह बोझ अकेले उठाना पड़ता।

लोगों की सेहत की ज़िम्मेदारी लोगों को ही सौंपते हुए, भारत ने अपने सामुदायिक मंचों को मज़बूत किया है। यह एक सोच-समझकर बनाया गया, विकेंद्रीकृत ढांचा है, जो योजनाकृत, निगरानी और जवाबदेही को स्थानीय लोगों के हाथों में सौंपता है। विलेज हेल्थ, सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमिटीज़ (वीएचएसएनसी), जन आरोग्य समितियां (जेएएस) और रोगी कल्याण समितियां (आरकेएस) ने पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में सक्रिय भागीदार बनाया है। शहरी इलाकों में, महिला आरोग्य समितियां (एमएएस) पारदर्शिता, जवाबदेही और भरोसेमंद प्रतिक्रिया के लिए समुदाय की आवाज़ को अहमियत देते हुए, महिलाओं को सामुदायिक आउटरीच के केंद्र में रखकर इस फ़ोकस को और गहरा करती हैं। वास्तविक स्वास्थ्य सुरक्षा का अर्थ है आज के खतरों के साथ-साथ कल के खतरों के लिए भी तैयार रहना। 2021 में 64,180 करोड़ रुपये के बजट के साथ शुरू की गई पीएम-एबीएचआईएम योजना सीधे तौर पर कोविड-19 से मिले सबक पर आधारित है, जैसे कि अचानक बढ़ने वाली ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता बनाना, लेबोरेटरी नेटवर्क को मज़बूत करना, बीमारियों की वास्तविक समय में निगरानी का दायरा बढ़ाना और वन हेल्थ शोध ढांचा विकसित करना। असल में, यह मुश्किल समय से मिले सबक को एक मज़बूत जन स्वास्थ्य प्रणाली में बदलने का काम है।

जब बीमारी के लिए अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत पड़ती है, तो आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई आर्थिक मदद प्रदान करता है, जिससे इलाज का खर्च परिवार के लिए भारी बोझ नहीं बनता। दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना होने के नाते, यह हर परिवार को हर साल द्वितीय और तृतीयक देखभाल के लिए 5 लाख रुपये तक की सुविधा देती है। यह सुरक्षा 2024 में 70 साल से ज़्यादा उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को भी दी गई, चाहे उनकी आय कुछ भी हो। इन सभी पहलों के पीछे एक डिजिटल आधार है, जिसके बिना इतने बड़े पैमाने पर व्यवस्था काम नहीं कर सकती। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत आभा आईडी, अंतर सचालित स्वास्थ्य जानकारी और यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस ने रिकॉर्ड को पोर्टेबल, पहुंच को आसान और सेवाओं के वितरण को और बेहतर बना दिया है। भारत की डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली की ओर बढ़ने के साथ ही अब तक लगभग 91 करोड़ आभा आईडी बनाई जा चुकी हैं। कुल मिलाकर, मुफ्त सेवाएं, सामुदायिक स्तर पर निदान, अग्रिम पंक्ति के विशेषज्ञ, रेफरल परिवहन, डायलिसिस, अस्पताल में भर्ती होने का खर्च और एक डिजिटल आधार, केवल योजनाओं का संग्रह नहीं हैं, बल्कि ये एक प्रणाली का निर्माण करते हैं। लिहाज़ा ये स्वास्थ्य संबंधी लाभ आकस्मिक नहीं हैं। ये सतत, कई स्तरों पर किए गए सार्वजनिक निवेश का कारगर परिणाम हैं। ये नतीजे अब अमूर्त नहीं हैं, वे भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। मातृ मृत्यु दर 2004-06 में प्रति लाख जीवित जन्मों पर 254 से घटकर 2022-24 में 87 हो गई है, जो एनएचपी 2017 के लक्ष्यों को पूरा करती है। 1990 से 2024 तक, भारत ने एमएमआर में 84त्न की कमी की है, जो वैश्विक स्तर पर 48त्न की गिरावट से लगभग दोगुनी है और इसी वजह से मातृ स्वास्थ्य और परिवार नियोजन में नेतृत्व के लिए यूएनएफपीए की मान्यता प्राप्त की है। व्यापक तस्वीर भी यही कहानी बयां करती है: नवीनतम एनएफएचएस के अनुसार, प्रजनन दर 2.0 तक पहुंच गई है, संस्थागत प्रसव 90.6त्न तक बढ़ गए हैं और पूर्ण टीकाकरण अब 98.6त्न है। ये एक ऐसी प्रणाली के संकेत हैं, जो रोकथाम, पहचान और प्रतिक्रिया करना सीख रही है। यही कारण है कि भारत की उन्मूलन उपलब्धियाँ महत्वपूर्ण हैं: 2015 में मातृ एवं नवजात टेटनस और 2024 तक ट्रेकोमा का सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में उन्मूलन। ऐसा करने वाला भारत दक्षिण-पूर्व एशिया का तीसरा देश बन गया है।

सर्राफ से बना चोर: प्रेमिकाओं के शौक पूरे करने के लिए 4.55 करोड़ की चोरी, प्रेमिका को एक कॉल करना पड़ा भारी

आर्यावर्त संवाददाता

गाजियाबाद। गाजियाबाद के आरडीसी स्थित तनिष्क शोरूम से साढ़े चार करोड़ रुपये से अधिक की ज्वेलरी चोरी का मास्टरमाइंड एक फोन कॉल से पुलिस के हत्थे चढ़ गया। कविनगर पुलिस ने इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी सेल्समैन नितिन वर्मा, उसके पिता संजय वर्मा और नितिन की प्रेमिका काजल को गिरफ्तार कर लिया है।

आरोपियों के कब्जे से 3.16 करोड़ रुपये कीमत के सोने के आभूषण और साढ़े छह लाख रुपये नकद बरामद किए गए हैं। डीसीपी सिटी धवल जायसवाल ने मंगलवार को प्रेसवार्ता में बताया कि 12 जून को तनिष्क शोरूम से करीब 4.55 करोड़ रुपये के गहने चोरी हुए थे। इस मामले में मोदीनगर के बुलाका पाड़ा

निवासी नितिन वर्मा, उसके पिता संजय वर्मा और नितिन की प्रेमिका काजल को गिरफ्तार किया गया है। वहीं फरार आरोपी चितरंजन उर्फ चिंटू निवासी मोदीनगर और उसकी प्रेमिका सानिया की तलाश में पुलिस टीम कानपुर भेजी गई है। दोनों पर 25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है।

सर्राफ से बना चोर, प्लानिंग के तहत की नौकरी

पुलिस पूछताछ में सामने आया कि नितिन वर्मा पेशे से सर्राफ है। वह मोदीनगर, कानपुर और गाजियाबाद की कई दुकानों पर जेवर साफ करने और गलाने का काम कर चुका है। उसने चोरी के इरादे से ही 5 मई को तनिष्क शोरूम में सेल्समैन की नौकरी शुरू की थी। एक माह तक उसने शोरूम की पूरी रेकी की और चोरी की योजना बनाई।

11 जून की रात को नितिन ने कैशियर गौतम राज, सुरक्षाकर्मी और अन्य सेल्समैन साथियों को अपनी शादी तय होने की बात कहकर पार्टी दी। सभी को जमकर शराब पिलाई। इसी दौरान उसने कैशियर गौतम राज की जेब से शोरूम की चाबी चुरा ली।

प्रेमिकाओं के शौक पूरे करने को की चोरी

डीसीपी ने बताया कि नितिन और चितरंजन ने अपनी-अपनी प्रेमिकाओं को रिझाने और उनके महंगे शौक पूरे करने के लिए शोरूम में चोरी की योजना बनाई थी। दोनों का इरादा चोरी के बाद विदेश भागने का था। इस खुलासे के लिए स्वॉट टीम को 50 हजार रुपये इनाम से पुरस्कृत किया गया है। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। बरामद ज्वेलरी की कीमत करीब 3.16 करोड़ रुपये आंकी गई है।

25 मिनट में उड़ाए तीन किलो सोने के जेवर

12 जून की सुबह करीब 7 बजे नितिन अपने साथी चितरंजन उर्फ चिंटू के साथ पहले संतोष अस्पताल पहुंचा। वहां से दोनों ने एक कैब बुक की और शोरूम से करीब 300 मीटर पहले सड़क पर उतर गए। पैदल शोरूम पहुंचकर नितिन ने शटर का ताला खोला। नितिन शोरूम में दाखिल हुआ जबकि चिंटू बाहर पहरा देता रहा। करीब 25 मिनट तक पहली मंजिल पर रखे कीमती सोने के आभूषण करीब 3 किलो चोरी कर बैग में भरे और दोनों मौके से फरार हो गए। सीसीटीवी में दोनों की हरकत कैद हो गई थी।

पिता को सौंपा माल, साली के घर छुपाए जेवर

चोरी के बाद दोनों कैब से मोदीनगर स्थित एक सरकारी स्कूल पहुंचे। वहां नितिन ने अपने पिता संजय वर्मा को बुलाया। कुछ जेवर पिता को थमाए और घर में न रखने की हिदायत दी। संजय वर्मा ने साथी चितरंजन को भी कुछ गहने दिए और ऋषिकेश में मिलने की बात कही। संजय वर्मा चोरी के आभूषणों से भरा बैग लेकर अपनी साली के घर पहुंचा। वहां बताया कि उसे कहीं बाहर जाना है और बैग लौटते समय ले जाएगा। पुलिस ने संजय को भागने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया और साली के घर से जेवर से भरा बैग बरामद कर लिया।

एक कॉल ने पहुंचाया सलाखों के पीछे

वारदात के बाद नितिन और चितरंजन अपनी-अपनी प्रेमिकाओं के साथ फरार हो गए। सभी ऋषिकेश पहुंचे। नितिन ने वहां एक राहगीर के मोबाइल फोन से अपनी प्रेमिका काजल को कॉल की। पुलिस ने नंबर को ट्रेस किया और लोकेशन के आधार पर नितिन व काजल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के ऋषिकेश पहुंचने की भनक लगते ही चितरंजन शॉपिंग के बहाने अपनी प्रेमिका सानिया के साथ फरार हो गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उसकी अंतिम लोकेशन कानपुर में मिली है।

युवती को बहला-फुसलाकर भगाने का आरोप, लाखों के जेवर और नकदी लेकर हुई फरार

सुलतानपुर। जिले के बल्दीराय थाना क्षेत्र में एक युवती को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और घर से लाखों रुपये के जेवरात व नकदी गायब होने का मामला सामने आया है। पीड़ित पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, वलीपुर चौकी क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने बल्दीराय थाने में दी गई तहरीर में आरोप लगाया कि 8 जून की शाम करीब 4.30 बजे गांव का ही युवक शिवपाल यादव पुत्र मुन्नाप्रसाद उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। पीड़ित के मुताबिक, बेटी घर से निकलते समय अपनी मां के कीमती जेवरात और बक्से में रखे ₹20 हजार नकद भी साथ ले गई। गायब सामान में चांदी की करधनी, चांदी का दसवन्द, चांदी की पाजेब, सोने की झुमकी, मंगलसूत्र, सोने का ठप्पा, कान का बाला और सोने की माथ बेदी शामिल बताई गई है।

ग्रेटर नोएडा में हैवान बना पति, पहले पत्नी के साथ पी शराब... फिर चुन्नी से गला घोंटकर ले ली जान

आर्यावर्त संवाददाता

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र में पति-पत्नी के पवित्र रिश्ते को शर्मसार करने वाली सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां एक युवक ने विवाद के बाद अपनी पत्नी की उसी की चुन्नी से गला घोंटकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया।

घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

9 साल पहले किया था प्रेम विवाह

पुलिस के अनुसार मृतका की पहचान कविता के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि कविता ने करीब 9 वर्ष पहले आरोपी मोहित से प्रेम विवाह किया था। मोहित मूल रूप से दादरी थाना क्षेत्र के चिटहेरा गांव का रहने वाला बताया जा रहा है और वर्तमान में वह पत्नी के साथ दादरी क्षेत्र के जारचा रोड पर रह रहा था।

दोनों के एक बेटा और एक बेटी हैं। शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि पति-पत्नी दोनों शराब पीने के आदी थे। घटना से पहले भी दोनों ने शराब पी थी, जिसके बाद किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया।

चुन्नी से घोंट दिया गला

थाना प्रभारी ने यह भी बताया कि पुलिस को डायल 112 के माध्यम से सूचना मिली थी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू की। पड़ोसियों ने बताया कि रात करीब 3 बजे के आसपास दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो रही थी, जिसके बाद उन्हें शांत करा दिया गया और वे अपने कमरे में सोने चले गए। लेकिन जब सुबह काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला, तो पड़ोसियों ने दरवाजा खोलकर देखा। अंदर पत्नी मृत अवस्था में पड़ी हुई मिली। वारदात के बाद आरोपी पति मौके से फरार है।

आरोपी की तलाश

दादरी थाना प्रभारी ने बताया कि मृतका कविता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्राथमिक जांच में पति-पत्नी के बीच विवाद के बाद हत्या की बात सामने आई है। वहीं, उसका पति मोहित घटना के बाद मौके से फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल परिजनों को इसकी सूचना दे दी गई है।

भीषण गर्मी से जूझ रहे ग्रामीण, 05 दिन से अंधेरा

कुड़वार/सुल्तानपुर। विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते 05 दिनों से क्षेत्र के पूरे तिलक गांव के लोग भीषण गर्मी से जूझ रहे है। बिजली विभाग केवल सांत्वना देता दिखाई दे रहा है।

बता दे कि 05 दिन पूर्व पूरे तिलक तिवारी गांव में लगा विद्युत परिवर्तक जल गया। जिसकी सूचना ग्रामीणों ने विभाग को दी। सूचना के बाद पहुंचे विभागीय कर्मियों ने विद्युत विभाग के स्टोर से रिपेयर ट्रांसफार्मर मंगवा कर लगाया जो एक घंटा भी राहत नहीं दे सका। दूसरे दिन भी फिर ट्रांसफार्मर आया और वही हुआ। विद्युत विभाग लगातार तीन ट्रांसफार्मर बदल चुका लेकिन ग्रामीणों को भीषण गर्मी से निजात नहीं मिल सकी। पूरा गांव अंधेरे में जीवन व्यतीत कर रहा है। जेई अवधेश मौर्य के अनुसार उनके द्वारा गर्मी की शुरुआत के पहले ही ट्रांसफार्मर को लोड के चलते 250 केवीए का करने का प्रस्ताव भेज दिया गया था। जो अभी अधीक्षण अभियंता अयोध्या मंडल के कार्यालय में पेंडिंग है।

बदायूं में भीषण हादसा : हाईवे पर रेस लगा रहे ट्रैक्टरों ने ई-रिक्शा को रौंदा, छह लोगों की मौत, दो घायल

आर्यावर्त संवाददाता

बदायूं। बदायूं के उझानी कोतवाली क्षेत्र में बुधवार दोपहर भीषण हादसा हो गया। दो ट्रैक्टर चालकों की लापरवाही से छह लोगों की मौत हो गई। दो अन्य लोग घायल हुए हैं। घायलों को राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने दोनों ट्रैक्टरों का कब्जे में लिया है। चालकों की तलाश शुरू कर दी है। हादसे की सूचना मिलते ही डीएम और एसएसपी भी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए।

भूलपुर क्षेत्र में हुआ हादसा

जानकारी के मुताबिक कछला और उझानी के बीच भूलपुर क्षेत्र में हाईवे पर दो ट्रैक्टर चालक रेस लगा रहे थे। तेज रफ्तार ट्रैक्टरों ने ई-रिक्शा को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ई-रिक्शा के परखच्चे उड़ गए। उसमें सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर आसपास के लोग जुट गए। पुलिस को सूचना दी गई।

ई-रिक्शा पर सवार थे सभी लोग

सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने घायलों को सीएचसी भेजा, जहां छह लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। दो घायलों को मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। मरने वाले सभी लोग ई-रिक्शा पर सवार थे। सीओ उझानी भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने घटना की जानकारी ली। ट्रैक्टर चालकों का पता लगाया जा रहा है। दोनों ट्रैक्टरों को कब्जे में लिया है।

मोहर्रम की मजलिसों का सिलसिला जारी

आर्यावर्त संवाददाता

सुलतानपुर। पहली मोहर्रम की मजलिस सुबह हुसैनिया नौतामीर गोराबारिक अमहट सुल्तानपुर में हुई जिनको मौलाना सैयद सिबतैन अब्बास रिजवी ने पढ़ा उन्होंने कहा कि जंगे आजादी के मौके पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था काश हुसैन जैसे हमें भी 72साथी मिल जाते तो मैं 24घंटे में भारत को आजाद करा देता हुसैन ने इन्सानियत को वह हौसला दिया है कि हुसैन की शहादत के बाद हर जालिम मजलूम से डरने लगा है जो इन्सान मरने को तैयार हो जाये उसे कभी कोई हरा नहीं सकता विजय हमेशा सच कीहोती है झूठ की नहीं हक पर रहकर जान देकर इन्सानियत को बचाना यह हमें हुसैन से मिला है आज दुनिया की सुपर पावर ताकतें अगर डरती हैं तो हुसैन वालोंसे हर हुसैनी खुदा के अलावा और किसी से नहीं डरता।यह जानकारी हैदर अब्बास खान अध्यक्ष हुसैनी शिया वेलफेयर एसोसिएशन सुल्तानपुर ने दी है।

बरेली में मंत्री के भतीजे की मांझे से गर्दन कटने के बाद जागी पुलिस, ताबड़तोड़ छापेमारी... अब पुलों पर करेगी पहरेदारी

आर्यावर्त संवाददाता

बरेली। उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में चाइनीज मांझे से गन्ना राज्यमंत्री संजय गंगवार के भतीजे की गर्दन कटने के बाद पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। गन्ना राज्यमंत्री संजय गंगवार के भतीजे आदित्य वीर सिंह गंगवार की गर्दन चाइनीज मांझे से कटने की घटना के बाद अब शहर के प्रमुख पुलों पर पुलिस की विशेष ड्यूटी लगा दी गई है। मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

दरअसल, सोमवार सुबह हुई इस घटना ने शहर में एक बार फिर प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के खतरे को सामने ला दिया। पीलीभीत के ललौरीखेड़ा ब्लॉक प्रमुख अजय वीर सिंह गंगवार के बेटे 15 वर्षीय आदित्य वीर सिंह स्कूटी से स्टेडियम की ओर से गांधी उद्यान जा रहे थे। जब वह श्यामगंज पुल से गुजर रहे थे, तभी अचानक हवा में फंसा चाइनीज मांझा उनकी गर्दन में उलझ गया। मांझा इतना तेज था कि इससे उनकी गर्दन के अलावा होंठ, कान, गाल और हाथ की एक अंगुली भी कट गई। आसपास मौजूद लोगों और पुलिस की मदद से तुरंत उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी प्लास्टिक सर्जरी की।

मांझा बेचने वालों और पतंग उड़ाने वालों की तलाश तेज

घटना को गंभीर मानते हुए श्यामगंज चौकी के दरोगा योगेश कुमार लोहकना ने बारादरी थाने में अज्ञात व्यक्ति, प्रतिबंधित मांझा बेचने वाले और पतंग उड़ाने वालों के खिलाफ हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस का कहना है कि प्रतिबंधित और जानलेवा चाइनीज मांझे का इस्तेमाल सीधे लोगों की जान को खतरे में डालता है, इसलिए इस मामले को सामान्य लापरवाही नहीं माना गया है। घटना के समय चौकी प्रभारी और पुलिसकर्मी क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और यह पता लगाया जा रहा है कि आखिर शहर में प्रतिबंध के बावजूद चाइनीज मांझा कहां से पहुंच रहा है। इधर, किला थाना क्षेत्र में पुलिस ने पतंग उड़ाने वाले करीब 12 लोगों को पकड़कर पूछताछ की। हालांकि जांच में उनके पास मिला मांझा चाइनीज नहीं निकला, जिसके बाद उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया गया।

आठ पुलों पर दो शिफ्ट में पुलिस तैनात

अब पुलिस प्रशासन ने शहर के प्रमुख पुलों पर विशेष निगरानी शुरू कर दी है। श्यामगंज, महादेव सेतु, हार्टमैन पुल, किला पुल, आईवीआरआई ओवरब्रिज, सेटेलाइट, अटल सेतु और लाल फाटक पुल पर दो-दो शिफ्ट में दो-दो सिपाहियों की तैनाती की गई है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, जरूरत पड़ने पर ड्रोन से भी निगरानी कराई जाएगी, ताकि पुलों और ऊंचे इलाकों में पतंग उड़ाने वालों पर नजर रखी जा सके। पहले ही दिन इस व्यवस्था का असर भी दिखा। शाम के समय एक कटी पतंग का चाइनीज मांझा सड़क से गुजर रहे वाहन चालकों की ओर बढ़ रहा था। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने समय रहते वाहन रोके और मांझा हटाकर संभावित हादसे को टाल दिया। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि प्रतिबंधित मांझे का इस्तेमाल न करें और इसकी बिक्री या उपयोग की जानकारी तुरंत पुलिस को दें, ताकि ऐसे हादसों को रोका जा सके।

फादर्स-डे से पहले बेटियों का अनोखा गिफ्ट... शादी से ठीक पहले बड़ी बेटी ने दी किडनी, छोटी ने लीवर डोनेट कर पिता को दिया नया जीवन

आर्यावर्त संवाददाता

गाजियाबाद। अक्सर कहा जाता है कि बेटियां परिवार की शान और अभिमान होती हैं, लेकिन गाजियाबाद के मोरटा गांव की दो बेटियों ने इसे सच साबित कर दिखाया है। जब उनके पिता के जीवन पर मौत का संकट मंडराया, तो दोनों बेटियां काल के सामने चट्टान की तरह खड़ी हो गईं। आगामी फादर्स डे से ठीक एक हफ्ते पहले, एक बेटी ने अपनी किडनी और दूसरी ने अपने लीवर का हिस्सा दान कर अपने पिता को नए जीवन का सबसे अनमोल तोहफा दिया है।

मोरटा गांव के रहने वाले 45 वर्षीय जयंत त्यागी (जो पूर्व में भाजपा के सेक्टर संयोजक भी रह चुके हैं) बेहद सात्विक और सामान्य जीवन जीते हैं। अचानक वे एक गंभीर बीमारी की चपेट में आ गए। डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि उनके

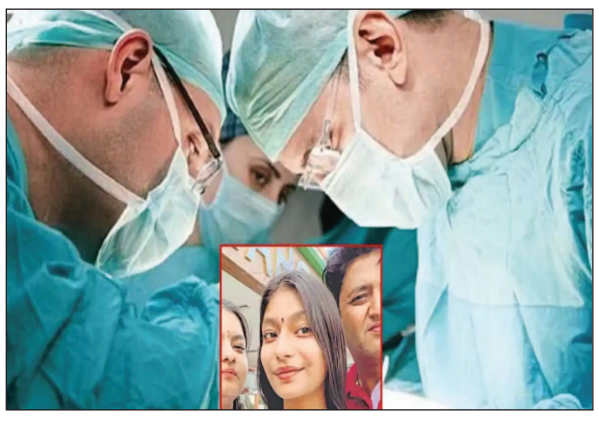

लीवर और किडनी दोनों खराब हो चुके हैं और उन्हें तुरंत ट्रांसप्लांट (प्रत्यारोपण) की जरूरत है। यह सुनते ही पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन इस कठिन घड़ी में उनकी दोनों बेटियां परिवार की सबसे बड़ी ढाल बनकर सामने आईं। हाल ही में बीटेक की पढ़ाई पूरी करने वाली बड़ी बेटी रिषिका त्यागी ने बिना सोचे अपनी एक किडनी पिता को दान करने का फैसला लिया। भावुक करने वाली बात यह है कि कुछ ही महीनों बाद रिषिका की शादी होने वाली है। जब रिषिका ने अपने इस फैसले की जानकारी अपने होने वाले ससुराल पक्ष को दी, तो उन्होंने शादी की परवाह न करते हुए रिषिका के इस साहसी कदम का पूरा समर्थन किया और उसका उत्साह बढ़ाया। वहीं, बीटेक प्रथम वर्ष में पढ़ने वाली छोटी बेटी खुशी ने भी अपने कदम पीछे नहीं खींचे और पिता को लीवर दान करने का ऐतिहासिक फैसला किया।

नोएडा के अस्पताल में हुआ जटिल ऑपरेशन, स्थिति अब सामान्य

दोनों बेटियों का सिर्फ एक ही संकल्प था- पापा को कुछ नहीं होने देंगे। डॉक्टरों की टीम ने परिवार के कई सदस्यों की जांच की थी, लेकिन दोनों बेटियों की रिपोर्ट सबसे सटीक बैठी। लंबी काउंसलिंग और सभी चिकित्सीय प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद, नोएडा के एक निजी अस्पताल में सोमवार को डॉक्टरों की टीम ने एक बेहद जटिल और लंबे ऑपरेशन के बाद सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया पूरी की। वर्तमान में जयंत त्यागी और उनकी दोनों बेटियों की हालत स्थिर और सामान्य बनी हुई है।

साहस और समर्पण को हर कोई कर रहा सलाम

जयंत त्यागी के छोटे भाई अमित रंजन ने बताया कि शुरुआत में परिवार बेटियों के स्वास्थ्य और भविष्य को लेकर बेहद चिंतित था, लेकिन बेटियों के इस अटूट भरोसे के आगे कि "पापा हैं तो सब कुछ है," सबको झुकना पड़ा। इस ऑपरेशन के दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी रक्तदान करने अस्पताल पहुंचे थे। भाजपा महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल समेत मोरटा गांव और संगठन से जुड़ा हर व्यक्ति इन दोनों बेटियों के साहस, त्याग और समर्पण को सलाम कर रहा है। यह कहानी समाज के लिए एक ऐसी मिसाल है जो बताती है कि बेटियां माता-पिता के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं।

एक माह तक गूंजता रहा 'ॐ नम : शिवाय', हवन-पूजन व भंडारे के साथ हुआ समापन

आर्यावर्त संवाददाता

कुड़वार/संवाददाता। क्षेत्र के गोविंदपुर स्थित प्राचीन गोविंदेश्वर महादेव मंदिर में पिछले एक माह से चल रहे अखंड 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र जाप का बुधवार को विधि-विधानपूर्वक समापन हो गया। 17 मई से प्रारंभ हुआ यह धार्मिक अनुष्ठान 15 जून तक निरंतर चलता रहा, जिसमें क्षेत्र के श्रद्धालुओं ने बढ़-चढ़कर सहभागिता की। समापन अवसर पर मंदिर परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन-पूजन का आयोजन किया गया। विद्वान आचार्यों ने भगवान शिव की आराधना कर क्षेत्र की सुख-समृद्धि, शांति और जनकल्याण की कामना की। हवन में श्रद्धालुओं ने आहुति देकर पुण्य लाभ अर्जित किया। पूरे मंदिर परिसर में भक्ति और आस्था का वातावरण बना रहा।

हवन-पूजन के उपरांत विशाल भंडारे का आयोजन किया गया,

जिसमें आसपास के गांवों तथा क्षेत्र से पहुंचे बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का पूजन-अर्चन कर परिवार की खुशहाली और मंगल की कामना की। मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि एक माह तक चले मंत्र जाप और धार्मिक कार्यक्रमों से क्षेत्र में आध्यात्मिक चेतना का संचार हुआ। कार्यक्रम के सफल आयोजन में ग्रामीणों और भक्तों का विशेष सहयोग रहा। पूरे आयोजन के दौरान श्रद्धा, भक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिला।

गर्मी में आइस्ड टी से क्यों बेहतर है दूध वाली गर्म चाय, आयुर्वेद से जानें

गर्मी कितनी ही हो चाय के शौकीन अपनी इस फेवरेट ड्रिंक को नजरअंदाज नहीं कर पाते हैं। वैसे आज का खानपान काफी अलग है। लोग गर्म दूध की चाय ही नहीं आइस टी को भी शौक से पीते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से गर्मी में इन दोनों में से किसे पीना बेस्ट है... चलिए आपको बताते हैं...

गर्मी के मौसम में ठंडी चीजें बड़े शौक से खाई और पी जाती हैं। लेकिन दूध वाली गर्म चाय के दीवाने भीषण गर्मी में भी इसे नजरअंदाज नहीं कर पाते हैं। वैसे इस ड्रिंक को पीने के तरीके काफी बदल गए हैं। इनमें से एक आइस डी भी है जो GenZ के बीच काफी पॉपुलर है। यहां हम दूध वाली गर्म चाय और आइस्ड टी के बीच कंपेरिजन करने जा रहे हैं। आयुर्वेद के हिसाब से गर्मी में किसे पीना ज्यादा सही है, ये जान लेना भी जरूरी है। दरअसल, गर्मी के मौसम में ठंडा पेय सभी को पसंद है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि आपके शरीर के लिए इस मौसम में सबसे अच्छा पेय कौन सा है?

आइस टी ठंडी है इसलिए गर्मी से तुरंत राहत देती है। वहीं दूध वाली चाय को पीने से थोड़ी देर के लिए बॉडी का तापमान बढ़ता है लेकिन बाद में ठंडक महसूस होती है। चलिए आपको आयुर्वेद के नजरिए से बताते हैं गर्मी में किसे पीना ज्यादा फायदेमंद है?

GenZ की पसंदीदा ड्रिंक आइस्ड टी

यह गर्मियों के मौसम में ठंडक देने वाला ऐसा ड्रिंक है जिसे बनाना भी आसान है और स्टोर करना भी। यह हाइड्रेटेड और सेहतमंद रहने का सबसे अच्छा तरीका है साथ ही कम कैलोरी वाला विकल्प भी है। यह ड्रिंक मुख्य रूप से पानी से बनता है और गर्मी के मौसम में पसीने के ज़रिए शरीर से निकले पानी की कमी को पूरा करता है।

आइस्ड टी के बेनिफिट

गर्मी से बचावः आइस्ड टी (ग्रीन टी और ब्लैक टी) पॉलीफेनॉल्स से भरपूर होती है जो आपकी त्वचा की कोशिकाओं को सूरज की क्षति और सनबर्न से बचाती है।

टेस्ट में भी बेस्टः इसमें कई फ्लेवर होते हैं, जिसके कारण इसे अपनी पसंद के हिसाब से तैयार किया जा सकता है।

बनाने का तरीका भी आसानः इसे बनाने के लिए गर्म पानी की जरूरत नहीं होती, यही वजह है कि इसे बनाना आसान है।

आइस्ड टी पर आयुर्वेद का नजरिया

नकली चीनी का यूजः आइस्ड टी में आमतौर पर ज़्यादा आर्टिफिशियल चीनी होती है, बेहतर होगा कि आप अपनी खुद की चाय बनाएं और उसमें खांड जैसे नेचुरल स्वीटनर मिलाएं।

कैफीन की मात्राः ब्लैक और ग्रीन आइस्ड टी में कैफीन होता है, जिसके सेवन से कई तरह के नकारात्मक शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ते हैं।

आइए जानते हैं आयुर्वेद क्या कहता है

आयुर्वेद कहता है कि जिस व्यक्ति के शरीर में तीन दोष (वात-पित्त-कफ) और पेट की पाचन अग्नि संतुलित हो, शरीर के अंग और धातुएं सही से काम करें और जिसका मन, आत्मा व इंद्रियां खुश हों।। असल में वो इंसान पूरी तरह स्वस्थ है।

डाइजेशन पर बुरा असरः आयुर्वेद कहता है कि ज्यादा ठंडा पेय आपकी पाचन क्रिया को कमजोर करता है, यह मेटाबोलिज्म को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए आइस्ड डी को ज्यादा पीना पेट के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। आयुर्वेद डॉक्टर चंचल शर्मा कहती हैं कि गर्मियों में ठंडे पेय के बजाय गुनगुना पेय लेना चाहिए, ये सुनने में जितना अटपटा लगता है उतना ही सत्य भी है।

ठंडा पेय आपको तुरंत ठंडक तो दे सकता है पर इसका ज्यादा सेवन आपकी पाचन क्रिया को धीमा कर सकता है इसी कारण ये पेट और गले में जलन भी पैदा करता है।

ध्यान रखें ये बातें

गर्मियों में बहुत ठंडी या बहुत गर्म चाय पीने के बजाय, गुनगुनी या हल्की गरम हर्बल टी पीनी चाहिए, हर्बल टी में बिल्कुल भी कैफीन नहीं होता है, इसलिए यह एक आइडियल ऑप्शन है। बताया जाता है कि गर्म ड्रिंक आपको गर्म नहीं रखता बल्कि इसकी तासीर आपके पेट को अंदर से ठंडा रखती है और आपके शरीर को लंबे समय तक हाइड्रेटेड रखती है।

ऊर्जा का स्रोतः हर्बल टी नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करने के बजाय शारीरिक कार्यों में बिना कैफीन के प्राकृतिक ऊर्जा देती है साथ ही यह मानसिक विकास और ब्लड संचार को भी प्रभावित करती है।

नेचुरल इलाजः चाय में इस्तेमाल होने वाले कुछ मसालों में जबरदस्त औषधीय गुण होते हैं। अदरक पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है, वहीं दालचीनी ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखती है।

एंटीऑक्सीडेंट से भरपूरः चाय में इस्तेमाल होने वाली आम औषधि यानी लौंग में दूसरे मसालों के मुकाबले सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं; साथ ही, इसमें सूजन कम करने और वायरस से लड़ने वाले गुण भी होते हैं। अगली बार जब आप गर्मी में डाइट कोक के लिए हाथ बढ़ाएं, तो जान लें कि आपके पास एक बेहतर विकल्प है।

रोजाना कहीं आने-जाने के दौरान त्वचा को प्रदूषण और टैन से बचाने के लिए असरदार तरीके

त्वचा

रोजाना कहीं भी आते-जाते हुए प्रदूषण और सूरज की किरणों का सामना करना पड़ता है, जो त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्रदूषण के कण और सूरज की किरणें त्वचा की चमक को कम कर सकती हैं और टैनिंग का कारण बन सकती हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपनी त्वचा को इन समस्याओं से बचा सकते हैं और त्वचा की देखभाल सही तरीके से कर सकते हैं।

धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन लगाएं

घर से कहीं भी बाहर जाते समय हमेशा एक अच्छी गुणवत्ता वाली धूप से बचाने वाली क्रीम लगाएं, जिसे सनस्क्रीन कहा जाता है। यह आपको सूरज की किरणों से बचाएगी और टैनिंग को रोकने में मदद करेगी। इस क्रीम को हर 2-3 घंटे में फिर से लगाएं, खासकर अगर आप लंबे समय तक बाहर रह रहे हैं। ध्यान दें कि क्रीम में सूरज से बचाने की अच्छी क्षमता हो, ताकि यह दिनभर प्रभावी रहे।

चेहरे को कपड़े से ढकें

अगर संभव हो तो अपने चेहरे को एक स्कार्फ या टोपी से ढकें। यह न केवल धूप से, बल्कि प्रदूषण से भी बचाव करेगा। अगर आप सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करते हैं तो चेहरे पर कपड़ा या मास्क भी पहन सकते हैं, जो आपके चेहरे को ढकता है और धूल-मिट्टी को रोकता है। इसके अलावा अगर आप बाइक चलाते हैं तो हेलमेट का उपयोग करें, जिससे आपका चेहरा सुरक्षित रहेगा और प्रदूषण का असर कम होगा।

को नमी दें

प्रदूषण आपकी त्वचा को सूखा और बेजान बना सकता है, इसलिए कहीं भी जाने से पहले एक अच्छा मॉइस्चराइजर लगाएं। यह आपकी त्वचा को नमी देगा और उसे मुलायम बनाएगा। अगर आपकी त्वचा तैलीय है तो हल्का जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर चुनें, जबकि सूखी त्वचा वालों के लिए क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर बेहतर रहेगा। नियमित उपयोग से आपकी त्वचा स्वस्थ और चमकदार बनी रहेगी, जिससे आप हर समय ताजा महसूस करेंगे।

हल्का मेकअप करें

अगर आप रोजाना कहीं भी जाएं तो भारी मेकअप करने से बचें, क्योंकि यह प्रदूषण के संपर्क में आने पर आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है। हल्का और प्राकृतिक मेकअप ही करें, जैसे कि हल्की क्रीम, काजल और लिप बाम। इससे आपकी त्वचा को हवा लगने का मौका मिलेगा और वह स्वस्थ रहेगी। इसके अलावा मेकअप के उत्पादों में एसपीएफ़ हो तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वे भी आपकी धूप से सुरक्षा कर सकेंगे।।

रोजाना सुबह और रात को अपने चेहरे को साफ करें, ताकि सारी गंदगी और प्रदूषण के कण हट जाएं। हफ्ते में 2 बार हल्का स्क्रब करें, ताकि मृत त्वचा हट जाए और त्वचा ताजगी महसूस करे। इन सरल तरीकों को अपनाकर आप अपनी त्वचा को प्रदूषण और टैनिंग से बचा सकते हैं और उसे स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। इससे त्वचा में एक अंदरूनी निखार आएगा और कभी भी चेहरा डल नहीं दिखेगा।

ब्लड की एक यूनिट भी कैसे बचा सकती है 3 लोगों की जान

ब्लड डोनेशन को लेकर भारत में लोगों के बीच कई गलतफहमियां फैली हुई है। लोग खुद से आगे आकर ब्लड डोनेशन में मदद नहीं करते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि एक यूनिट ब्लड भी किसी की जिंदगी बचाने में अहम रोल निभा सकता है।

रक्तदान शिविरों में अक्सर यह बात कही जाती है कि "आपका एक यूनिट ब्लड तीन लोगों की जान बचा सकता है।" पर क्या वास्तव में ऐसा संभव है? आखिर एक व्यक्ति द्वारा दान किया गया ब्लड तीन अलग-अलग मरीजों के काम कैसे आ सकता है? विशेषज्ञों के अनुसार इसके पीछे आधुनिक ब्लड बैंकिंग और रक्त पृथक्करण (ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन) की वैज्ञानिक प्रक्रिया काम करती है।

हर साल भारत में लाखों लोगों को दुर्घटनाएं, सर्जरी, कैंसर का इलाज, जन्म से जुड़ी जटिलताएं और ब्लड विकारों के कारण ब्लड की जरूरत होती है। ऐसे में रक्तदान जीवन बचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन जाता है।

एक यूनिट ब्लड से क्या होता है?

डॉ. उमा रानी, डायरेक्टर पैथोलॉजी, एशियन हॉस्पिटल बताती हैं कि जब कोई व्यक्ति ब्लड का दान करता है, तो उससे आमतौर पर लगभग 350 से 450 मिलीलीटर ब्लड लिया जाता है। पहले इस पूरे ब्लड (Whole Blood) को एक ही मरीज को चढ़ाया जाता था। लेकिन आधुनिक तकनीक ने इस प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बना दिया है। ब्लड बैंक में दान किए गए ब्लड को विशेष मशीनों की मदद से तीन प्रमुख घटकों में अलग किया जाता है, रेड ब्लड सेल्स (RBC), प्लाज्मा और प्लेटलेट्स। ये तीनों घटक अलग-अलग प्रकार के मरीजों के इलाज में इस्तेमाल किए जाते हैं।

तीन मरीजों के लिए कैसे उपयोगी होता है ब्लड?

रेड ब्लड सेल्स का उपयोग उन मरीजों में किया जाता है जिनमें खून की कमी होती है, जैसे गंभीर एनीमिया, बड़ी सर्जरी या दुर्घटना के शिकार मरीज। प्लाज्मा ब्लड का तरल हिस्सा होता है, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रोटीन और क्लॉटिंग फैक्टर मौजूद होते हैं। इसका उपयोग लीवर रोग, गंभीर जलन और रक्तस्राव से जूझ रहे मरीजों के उपचार में किया जाता है। वहीं प्लेटलेट्स का इस्तेमाल डेंगू, कैंसर, बोन मैरो रोग और कीमोथेरेपी से गुजर रहे मरीजों में किया जाता है, जहां प्लेटलेट्स की संख्या खतरनाक स्तर तक गिर जाती है। यही कारण है कि एक यूनिट ब्लड के अलग-अलग हिस्से तीन अलग मरीजों तक पहुंच सकते हैं और उनकी जान बचाने में मदद कर सकते हैं।

रक्तदान को लेकर लोगों में हैं कई भ्रम

विशेषज्ञों का कहना है कि रक्तदान को लेकर आज भी लोगों के मन में कई तरह की गलतफहमियां हैं। कुछ लोगों को लगता है कि इसे डोनेट करने से कमजोरी आ जाती है

या शरीर में खून की कमी हो जाती है। जबकि चिकित्सा विज्ञान इसके विपरीत बताता है। डॉ. उमा रानी, डायरेक्टर पैथोलॉजी, एशियन हॉस्पिटल कहती हैं, "एक स्वस्थ व्यक्ति द्वारा किया गया ब्लड डोनेशन पूरी तरह सेफ प्रोसेस है। शरीर कुछ ही घंटों में ब्लड के तरल हिस्से की भरपाई शुरू कर देता है और कुछ सप्ताह में ब्लड कोशिकाएं भी सामान्य स्तर पर पहुंच जाती हैं। रक्तदान से स्थाई कमजोरी नहीं आती।" वे बताते हैं कि ब्लड डोनेशन के लिए व्यक्ति की उम्र सामान्यतः 18 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसका वजन कम से कम 45 से 50 किलोग्राम होना चाहिए।

क्यों बनी रहती है ब्लड की कमी?

भारत में खुद से ब्लड डोनेट करने वालों की संख्या बढ़ने के बावजूद कई अस्पतालों और ब्लड बैंकों को समय-समय पर ब्लड की कमी का सामना करना पड़ता है। गर्मी, त्योहारों और छुट्टियों के दौरान रक्तदान में गिरावट देखने को मिलती है, जबकि मरीजों की जरूरत लगातार बनी रहती है।

डॉ. कहती हैं, "लोगों को समझना चाहिए कि ब्लड किसी फैक्ट्री में नहीं बनता। इसकी उपलब्धता पूरी तरह मानव दान पर निर्भर करती है। यदि स्वस्थ लोग नियमित रूप से रक्तदान करें तो हजारों मरीजों को समय पर जीवन रक्षक उपचार मिल सकता है।"

ब्लड डोनेशन से पहले और बाद में क्या करें?

विशेषज्ञ रक्तदान से पहले पर्याप्त पानी पीने, हल्का भोजन करने और अच्छी नींद लेने की सलाह देते हैं। रक्तदान के बाद कुछ समय आराम करना चाहिए और दिनभर पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लेना चाहिए। एक यूनिट ब्लड सही में तीन लोगों तक जीवन की उम्मीद पहुंचा सकती है।

इसका कारण ब्लड के विभिन्न घटकों को अलग-अलग मरीजों में उपयोग करने की आधुनिक चिकित्सा तकनीक है। विशेषज्ञों का कहना है कि नियमित और स्वैच्छिक रक्तदान न केवल सुरक्षित है, बल्कि यह समाज के लिए सबसे बड़ा मानवीय योगदान भी है। एक छोटा-सा प्रयास किसी के लिए नई जिंदगी का कारण बन सकता है।

बाजार की उठापटक में कैसे बचाएं अपनी पूंजी? जानिए मल्टी-फैक्टर फंड की रणनीति

शेयर बाजार में बढ़ते उतार-चढ़ाव के बीच मल्टी-फैक्टर फंड निवेशकों के लिए नया विकल्प बनकर उभरे हैं। जानिए ये फंड कैसे काम करते हैं, किन निवेशकों के लिए उपयुक्त हैं और इनमें निवेश से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

प्रयागराज में रहने वाले अमित कुमार पिछले कुछ दिनों से सुबह की चाय चैन से नहीं पी पा रहे हैं। वजह है शेयर बाजार का मौजूदा मिजाज। कुछ दिन पहले तक जब छोटे और मझोले शेयर रॉकेट की तरह भाग रहे थे। पिछले हफ्ते जैसे ही बड़ी कंपनियों ने कमान संभाली और छोटे शेयरों में मुनाफावसूली हुई, अमित के पोर्टफोलियो का रंग हरे से लाल हो गया।

आज के बाजार में बार-बार बदलते चक्र को भांपना और सही समय पर सही दांव लगाना किसी आम निवेशक के बस की बात नहीं है। इसीलिए एक अचूक रणनीति तेजी से लोकप्रिय हो रही है, जिसे मल्टी-फैक्टर फंड कहा जाता है।

क्या होते हैं ये मल्टी-फैक्टर फंड?

पारंपरिक म्यूचुअल फंड कंपनियों के आकार यानी उनके कुल बाजार मूल्य के हिसाब से शेयरों का चुनाव करते हैं। इस ढर्रे के विपरीत मल्टी-फैक्टर फंड इस बात पर ध्यान नहीं देते कि कोई कंपनी कितनी बड़ी है, बल्कि वे कंपनी के कामकाज के तरीके और उसके बर्ताव का आकलन करते हैं। इसके लिए वे कुछ ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित मजबूत कारकों को चुनते हैं।

ये फैक्टर ऐसे मजबूत स्तंभ हैं, जो जोखिम को कम करते हुए बेहतर रिटर्न देने के लिए जाने जाते हैं। पारंपरिक सूचकांकों के पीछे भागने के बजाय, यह फंड कई मजबूत कारकों, जैसे कंपनी का वास्तविक मूल्य, गुणवत्ता, रफ्तार, या उतार-चढ़ाव की स्थिरता, को एक साथ मिलाकर एक बेहद मजबूत पोर्टफोलियो तैयार करता है।

यह रणनीति काम कैसे करती है?

पारंपरिक म्यूचुअल फंड काफी हद तक फंड मैनेजर के अनुभव, अनुमान और व्यक्तिगत नजरिये पर निर्भर करते हैं। वहीं, मल्टी-फैक्टर फंड मानवीय भावनाओं, डर और लालच को पूरी तरह से किनारे कर देते हैं। यह व्यवस्था पूरी तरह से कड़े नियमों और कंप्यूटर आधारित गणितीय प्रणाली पर काम करती है।

इसकी पूरी प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी होती है

यह फंड बाजार के दो या दो से अधिक प्रमाणित स्तंभों को एक साथ चुनता है। इसके मुख्य चार स्तंभ हैं- गुणवत्ता (कम कर्ज और अधिक मुनाफा), वास्तविक मूल्य (सस्ते दामों पर मिलने वाले अच्छे शेयर), रफ्तार (तेजी से ऊपर की ओर भागते शेयर) और कम उतार-चढ़ाव (स्थिर शेयर जो बाजार के झटकों में ज्यादा नहीं डगमगाते)।

एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली पूरे शेयर बाजार को खंगालती है। यह समाचारों की सुर्खियों को नजरअंदाज कर केवल उन्हीं शेयरों को चुनती है, जो एक साथ कई कसौटियों पर खरे उतरते हैं।

पोर्टफोलियो को हमेशा धारदार बनाए रखने के लिए, यह फंड हर तीन या छह महीने में खुद-ब-खुद बदलाव करता है।

इस उतार-चढ़ाव में आपके लिए कौन-सा मिश्रण सही है?

आक्रामक निवेशक: रफ्तार+गुणवत्ता

यदि आप बाजार के मौजूदा हिचकोलों से नहीं डरते और लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं, तो यह मिश्रण आपके लिए है। रफ्तार आपको तेजी का पूरा फायदा दिलाएगी, जबकि गुणवत्ता यह पक्का करेगी कि आपका पैसा केवल मजबूत बुनियादी ढांचे वाली कंपनियों में ही लगे।

संतुलित निवेशक: गुणवत्ता+वास्तविक मूल्य

यह उन आम निवेशकों के लिए है, जो आज की उथल-पुथल के बीच रात को चैन की नींद सोना चाहते हैं। इसमें आपको साफ-सुथरी कंपनियां भी मिलती हैं और वे सही तथा किफायती दामों पर भी हासिल होती हैं।

रूढ़िवादी निवेशक: कम उतार-चढ़ाव+गुणवत्ता

अगर आपका मुख्य उद्देश्य अपनी पूंजी को बाजार के दौरों से बचाना है, तो यह मिश्रण आज के बाजार में एक शॉक-एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। आपका पैसा लगातार लाभांश देने वाली बेहद स्थिर कंपनियों में सुरक्षित रहता है।

इन बातों का रखें ध्यान

कंपनियां अक्सर इन फंडों को पुराने आंकड़ों की शानदार रिपोर्ट दिखाकर बेचती हैं। बाजार के बड़े बदलावों के दौरान ऐसा भी हो सकता है कि दो अलग-अलग स्तंभ कुछ समय के लिए एक साथ सुस्त पड़ जाएं। हर 3-6 महीने में पोर्टफोलियो की कड़ाई से छंटनी होती है। इससे प्रबंधन का खर्च बढ़ सकता है। फैक्टर रणनीतियों में 30% तक का आवंटन करें।

ईपीएफओ को झटका! कर्मचारी से वापस नहीं लिया जा सकता पीएफ का पैसा, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

पीएफ खातधारकों को बड़ी राहत देते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट ने कहा है कि कर्मचारी को दिया गया पीएफ वापस नहीं लिया जा सकता। कोर्ट के अनुसार नियमों के उल्लंघन की जिम्मेदारी नियोक्ता और पीएफ ट्रस्ट की होगी।

ईपीएफओ खाताधारकों के लिए तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि कर्मचारी को एक बार भुगतान किया गया पीएफ का पैसा वापस नहीं लिया जा सकता। यदि पीएफ भुगतान में किसी तरह का नियम उल्लंघन हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी नियोक्ता और संबंधित पीएफ ट्रस्ट की होगी, कर्मचारी की नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा कि ईपीएफओ कर्मचारी से रिकवरी नहीं कर सकता और जरूरत पड़ने पर कंपनी या ट्रस्ट के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला जेवी नृपेंद्र राव नाम के एक कर्मचारी से जुड़ा है, जो एक ऐसी कंपनी में काम करते थे जिसके पास अपना पीएफ ट्रस्ट था। इस ट्रस्ट को 1981 से एक्सेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट का दर्जा मिला हुआ था। हालांकि 1 मार्च 2023 को यह दर्जा वापस कर दिया गया। इसके बाद 21 जुलाई 2023 को ट्रस्ट ने कर्मचारी को करीब 2.150 करोड़ रुपये का पीएफ भुगतान किया। कर्मचारी को लगभग 70 लाख रुपये और मिलने थे। इस दौरान ट्रस्ट का कुछ पैसा यस बैंक बॉन्ड्स में निवेश था, जो आरबीआई के आदेशों के बाद फंस गया था। बाद में ईपीएफओ ने दावा किया कि एक्सेम्प्शन खत्म होने के बाद सीधे कर्मचारी को पीएफ भुगतान करना नियमों के खिलाफ था और कर्मचारी से रकम ब्याज सहित वापस मांगी जानी चाहिए।

ईपीएफओ ने भेजा रिकवरी नोटिस

मामले में ईपीएफओ ने 17 फरवरी 2025 को कर्मचारी के खिलाफ रिकवरी नोटिस जारी कर दिया। विभाग का कहना था कि नियमों के अनुसार, एक्सेम्प्शन खत्म होने के बाद पीएफ की राशि पहले ईपीएफओ को ट्रांसफर की जानी चाहिए थी। इसके बाद ही कर्मचारी को भुगतान किया जा सकता था। इसी आधार पर कर्मचारी से रकम वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की गई। हालांकि कर्मचारी ने इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनका तर्क था कि उन्हें कानूनी रूप से पीएफ का भुगतान किया गया था और यदि कोई प्रशासनिक या प्रक्रियागत गलती हुई है तो उसकी जिम्मेदारी कंपनी और ट्रस्ट की है, कर्मचारी की नहीं।

हाई कोर्ट ने क्यों दी कर्मचारी को राहत?

सुनवाई के बाद तेलंगाना हाई कोर्ट ने कर्मचारी के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि पीएफ की राशि कर्मचारी का कानूनी अधिकार है और उसे वापस मांगना उचित नहीं है। अदालत ने माना कि एक्सेंप्शन खत्म होने के बाद पीएफ फंड को ईपीएफओ के पास ट्रांसफर करने की जिम्मेदारी पूरी तरह कंपनी और उसके ट्रस्ट की थी। यदि इसमें कोई नियम उल्लंघन हुआ है तो कार्रवाई मैनेजमेंट और ट्रस्ट के खिलाफ होनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि रिकवरी नोटिस जारी करने से पहले कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दिया गया, जो नियमों का उल्लंघन है। इसी आधार पर अदालत ने ईपीएफओ के रिकवरी नोटिस रद्द कर दिए और स्पष्ट किया कि विभाग कर्मचारी नहीं बल्कि संबंधित प्रबंधन और ट्रस्ट के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।

फ्रांस में कनाडा के कार्नी और यूएई के नाहयान से मिले पीएम मोदी, क्या हुई बात? एक-एक डिटेल

वॉशिंगटन, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार (16 जून) को फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कनाडा प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद बिन सुल्तान अल नाहयान के साथ ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर मुलाकात। इस दौरान नेताओं ने व्यापार, विकास समेत तमाम मुद्दों पर बातचीत की।

पीएम मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान दोनों नेताओं ने पिछले साल हुई यात्राओं के बाद भारत-ब्रिटेन संबंधों में आई तेजी और प्रगति की समीक्षा की। नेताओं ने Vision 2035 के तहत व्यापार, आर्थिक विकास, रक्षा एवं सुरक्षा, जलवायु कार्रवाई, हरित ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों में हुई प्रगति का स्वागत किया गया।

दोनों नेताओं ने भारत-यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते को जल्द लागू करने की उम्मीद जताई। शिक्षा क्षेत्र में बढ़ते सहयोग पर संतोष व्यक्त किया गया। University of Liverpool द्वारा बेंगलुरु में कैंपस स्थापित करने की दिशा में हुई प्रगति का स्वागत किया गया। इसके साथ ही University of York और University of Bristol द्वारा मुंबई में कैंपस स्थापित करने की पहल का भी जिक्र किया गया।

प्रधानमंत्री मोदी ने इस साल दिल्ली में आयोजित AI Impact Summit में ब्रिटेन की मजबूत भागीदारी के लिए प्रधानमंत्री स्टार्मर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने IndiaUK Technology Security

बेंजामिन नेतन्याहू के बुरे दिन शुरू? 48 घंटे में इजराइल को अमेरिका ने दिए 4 बड़े झटके

तेल अवीव, एजेंसी। ईरान समझौते में अलग-थलग पड़े इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। पिछले 48 घंटों में टीम नेतन्याहू को 4 बड़े झटके लगे हैं। ये सभी झटके उसे अमेरिका ने दिए हैं। मंगलवार (16 जून) को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम कह दिया कि अगर मैं नहीं होता, तो इजराइल बर्बाद हो जाता। ट्रंप ने इजराइल को सीरिया से भी कमजोर राष्ट्र बताया है। ट्रंप के मुताबिक हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल से बेहतर सीरिया लड़ सकता है।

नेतन्याहू के लिए ट्रंप का यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि अक्टूबर 2026 में इजराइल में प्रधानमंत्री का चुनाव प्रस्तावित है। अब तक नेतन्याहू अमेरिका के भरोसे इस चुनाव में जीत की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अब वे पूरी तरह से

साइडलाइन हो गए हैं।

इजराइल को बैक टू बैक 4 बड़े झटके लगे

1- ईरान डील में अमेरिका ने इजराइल की शर्तों को शामिल नहीं किया है। इजराइल चाहता था कि ईरान समझौते में लंबी दूरी की मिसाइलों के निर्माण के मुद्दे को भी शामिल किया जाए। इसके अलावा इजराइल की कोशिश खाड़ी देशों को अब्राहम समझौते में शामिल कराने की भी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है।

2- इजराइल ने अमेरिका से डील को लेकर जिस एमओयू पर साइन होने हैं, उसकी एक कॉपी मांगी थी। अमेरिका ने इजराइल को देने से इनकार कर दिया है। इतना ही नहीं, पेरिस में ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ नहीं लड़ सकता है।

3। अमेरिकी मीडिया सीएनएन ने मंगलवार (16 जून) को एक रिपोर्ट की। इसके मुताबिक इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलना चाहते हैं लेकिन व्हाइट हाउस ने अभी उन्हें मिलने का वक्त नहीं दिया है। डील के बाद उन्हें मिलने का वक्त दिया जा सकता है।

4- हार्तेज के मुताबिक इजराइल के रक्षा मंत्री बेन ग्वीर को अमेरिका ने वीजा देने से इनकार कर दिया है। ग्वीर अमेरिका के मियामी जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें आसानी से स्पेशल वीजा नहीं दिया गया। इसे इजराइल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

अमेरिका ने नेतन्याहू को अकेला क्यों छोड़ा?

ईरान युद्ध की शुरुआत में इजराइल और अमेरिका साथ थे, लेकिन समझौते के दौरान अमेरिका ने उसे अकेला छोड़ दिया। दरअसल, इजराइल ईरान से कोई समझौता नहीं चाहता था। दूसरी तरफ, खाड़ी के कई देश ईरान से समझौते के पक्ष में थे। इनमें सऊदी अरब, यूएई, कतर और कुवैत प्रमुख रूप से शामिल हैं। नाटो देश तुर्की ने भी समझौते का रास्ता अपनाने की बात कही थी।

इतना ही नहीं, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को यह भरोसा दिलाया था कि जंग शुरू होते ही ईरान में तख्तापलट हो जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। इसके कारण ट्रंप ने नेतन्याहू पर भरोसा करना छोड़ दिया। अमेरिका के शीर्ष वार्ताकार और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी इजराइल के विरोध में हैं। नेतन्याहू के अलग-थलग पड़ने का यह भी एक मुख्य कारण है।

कनाडा में लॉरेंस गैंग पर बड़ी कार्रवाई, शूटर किंगरा को डिपोर्ट करेगी पुलिस, एक साथ 400 केस भी खोले

कनाडा। कनाडा में भारत के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से जुड़े एक शूटर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। कनाडा के इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी बोर्ड ने बिश्नोई गैंग के लिए गोली चलाने वाले भारतीय नागरिक अबजीत किंगरा को देश से बाहर निकालने यानी डिपोर्ट करने का आदेश दिया है। अबजीत किंगरा साल 2018 में स्टडी परमिट पर कनाडा पहुंचा था। आरोप है कि कनाडा पहुंचने के बाद वह धीरे-धीरे बिश्नोई गैंग के संपर्क में आया और गैंग के लिए काम करने लगा। जांच एजेंसियों के मुताबिक, उसने ब्रिटिश कोलंबिया के कोलवुड इलाके में एक घर पर बिश्नोई गैंग के इशारे पर फायरिंग की थी।

सितंबर 2024 में हुई इस वारदात में किंगरा ने कथित तौर पर पीड़ित के घर पर करीब 14 गोलियां

चलाईं, जबकि उसके साथी ने घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी थी। यह हमला पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों के घर पर हुआ था। घटना के बाद बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी जारी किया था, जिसमें फायरिंग की जिम्मेदारी लेने की कोशिश की गई थी।

बिश्नोई गैंग में कैसे शामिल हुआ था किंगरा?

कनाडाई जांच एजेंसियों के मुताबिक, किंगरा को एक मूविंग कंपनी में काम करने के दौरान गैंग के लोगों ने अपने साथ जोड़ा। किंगरा ने सुनवाई के दौरान दावा किया कि उसे सिर्फ पैसे का लालच देकर इस वारदात में शामिल किया गया था और उसे नहीं पता था कि वह बिश्नोई गैंग के लिए काम कर रहा है। उसने कहा कि वह अपने माता-पिता को पैसे भेजना चाहता था और इसी वजह से वह इस अपराध में शामिल हो गया। हालांकि कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी (CBSA) ने कहा कि संगठित गैंग अपने सदस्यों को इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि छोटे स्तर के लोग केवल अपने ऊपर वाले व्यक्ति को जानते हैं। इमिग्रेशन बोर्ड ने अपने फैसले में कहा कि बिश्नोई गैंग एक संगठित आपराधिक संगठन है, जो हत्या, गोलीबारी, आगजनी, धमकी और जबरन वसूली जैसे अपराधों में शामिल रहा है।

एक साथ 400 से ज्यादा मामलों की जांच शुरू

कनाडाई एजेंसियों के अनुसार, बिश्नोई गैंग ने वहां भारतीय मूल के कारोबारियों, सिंगर्स और अन्य लोगों को निशाना बनाकर धमकी भरे कॉल, मैसेज और सोशल मीडिया के जरिए पैसे की मांग की। पीड़ितों को हिंसा और संपत्ति नुकसान की धमकियां दी गईं। कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी ने बताया कि एक्सटॉर्शन और गैंग हिंसा से जुड़े 400 से ज्यादा मामलों की जांच शुरू की गई हैं और कई संदिग्धों को देश से बाहर किया जा चुका है।

जांच एजेंसियों का कहना है कि बिश्नोई गैंग की गतिविधियां कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा, मैनिटोबा और ओंटारियो जैसे इलाकों में ज्यादा सक्रिय रही हैं। गैंग पर ड्रग तस्करी, हत्या की सुपारी और वसूली जैसे अपराधों में शामिल होने के आरोप हैं। कनाडाई अधिकारियों ने यह भी कहा कि जेल में बंद होने के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई अपने नेटवर्क को चलाने और नए युवाओं को जोड़ने की कोशिश करता रहा है।

किंगरा के दोस्त विक्रम को खोज रही पुलिस

किंगरा फिलहाल छह साल की सजा काट रहा है। उसके खिलाफ दूसरे हमले से जुड़ा मामला भी चल रहा है। डिपोर्टेशन आदेश के खिलाफ किंगरा अपील करने की तैयारी में है। उसने दावा किया है कि अगर उसे भारत भेजा गया तो बिश्नोई गैंग उसे नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि इमिग्रेशन बोर्ड ने कहा कि उसने अपने इस दावे के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया।

इस पूरे मामले में विक्रम शर्मा नाम का एक और भारतीय नागरिक भी आरोपी है। आरोप है कि वह किंगरा के साथ इस हमले में शामिल था। वारदात के बाद विक्रम शर्मा कनाडा छोड़कर फरार हो गया और उसके भारत भाग जाने की आशंका जताई जा रही है। कनाडाई एजेंसियां उसकी तलाश कर रही हैं। कनाडा में बिश्नोई गैंग के खिलाफ चल रही कार्रवाई को वहां बढ़ते एक्सटॉर्शन और गैंग हिंसा पर बड़ा प्रहार माना जा रहा है।

40 मिनट में भूकंप के 8 बड़े झटकों से चीन में हड़कंप, एक की मौत... इमरजेंसी अलर्ट जारी

बीजिंग, एजेंसी। चीन के नॉर्थ-वेस्ट क्षेत्र के किंघाई प्रांत में 40 मिनट के भीतर भूकंप के 8 झटके महसूस किए गए। इनमें सबसे शक्तिशाली झटके की तीव्रता 6।3 मापी गई। भूकंप की गहराई जमीन से 10 किलोमीटर नीचे बताई जा रही है। चीन की स्थानीय मीडिया के मुताबिक, प्रशासन ने आनन-फानन में प्रभावित इलाके में इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही, राहत और बचाव कार्यों के लिए आपातकालीन दलों को तैनात किया गया है। चीन के समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक, किंघाई प्रांत में मंगलवार को स्थानीय समयानुसार शाम 6:40 बजे भूकंप का पहला झटका महसूस किया गया। भूकंप का केंद्र प्रांत की राजधानी शियांग से लगभग 567 किलोमीटर दूर स्थित बताया गया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक भूकंप में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सरकार ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया है। वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए पास के कोयला खादानों से लोगों को वापस बुलाया गया है। सरकार जान-माल की हानि के बारे में अधिक जानकारी जुटा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक राहत एवं बचाव कार्यों के लिए 2 स्पेशल गाड़ी और 10 कर्मी को घटनास्थल पर भेजा गया है। हताहतों की संख्या देखने के बाद स्थानीय प्रशासन आगे का फैसला लेगी। नॉर्थ-वेस्ट चीन का यह इलाका तिब्बती पठार के किनारे स्थित है, जिसे भूवैज्ञानिक दृष्टि से एक जटिल क्षेत्र माना जाता है। किंघाई प्रांत भारतीय और यूरेशियन विवर्तनिक प्लेटों के टकराव के कारण भूकंपीय गतिविधियों के प्रति संवेदनशील माना जाता है।

बिहार चुनाव में पार्टियों को मिला 281 करोड़ का चंदा, कितने किए खर्च?

पटना। बिहार में पिछले साल (2025) में विधानसभा चुनाव हुए थे। जिसमें तमाम राजनीतिक पार्टियों ने भाग लिया था। क्या आप जानते हैं कि इस दौरान इन पार्टियों ने कितना चंदा जुटाया था और सबसे ज्यादा पैसा कहां खर्च किया गया। चलिए आपको बताते हैं। राजनीतिक दलों ने कुल 281.32 करोड़ रुपये का चंदा इकट्ठा किया था और 193.47 करोड़ रुपये खर्च किए। जिसमें सबसे ज़्यादा नेताओं के चुनाव प्रचार पर खर्च हुआ। एसोसिएशन फोर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है।

दरअसल ADR की रिपोर्ट में पांच राष्ट्रीय पार्टियों और पांच क्षेत्रीय पार्टियों द्वारा दाखिल खर्च के ब्योरों का विश्लेषण किया गया। राष्ट्रीय पार्टियों बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (आप), बहुजन समाज पार्टी (बसपा) और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) वहीं क्षेत्रीय पार्टियों जिनमें राष्ट्रीय जनता दल (राजद), जनता दल यूनाइटेड (जदयू), लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), एआईएमआईएम और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) शामिल थीं। रिपोर्ट के मुताबिक 10 पार्टियों ने मिलकर चंदा के तौर पर 281.323 करोड़ रुपये जुटाये, जबकि उनका कुल खर्च 193। 466 करोड़ रुपये रहाय इस तरह जमा किए गए फंड और बताए गए खर्च के बीच करीब 88 करोड़ रुपये का अंतर रहा। राजनीतिक दलों के कुल खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा चुनाव प्रचार पर गया। पार्टियों ने प्रचार में 100.429 करोड़ रुपए खर्च किए जो कुल खर्च का 36.68 प्रतिशत है। पार्टियों ने नेताओं की यात्रा पर 79.539 करोड़ रुपये खर्च किए। वहीं उम्मीदवारों को एकमुश्त रकम के तौर पर 62.07 करोड़ रुपये बांटे गए। ADR की रिपोर्ट में बताया गया है कि सोशल मीडिया मंच और दूसरे डिजिटल माध्यमों से वर्चुअल प्रचार पर 13। 074 करोड़ रुपये खर्च हुए, जबकि पार्टियों ने चुनाव आयोग के निर्देशानुसार उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड को प्रकाशित करने पर 3। 886 करोड़ रुपये खर्च किए। वहीं अन्य खर्च 14.804 करोड़ रुपये रहे। रिपोर्ट के मुताबिक कुल खर्च का 29.05 फीसदी हिस्सा यात्रा पर खर्च किया गया। इस तरह, प्रचार के बाद यह चुनावी खर्च का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा बन गया।

बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 161 राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया, जिनमें 6 राष्ट्रीय दल, 10 क्षेत्रीय दल और 145 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल शामिल थे। हालांकि यह विश्लेषण केवल उन 10 प्रमुख दलों तक ही सीमित था, जिनके खर्च का ब्योरा उपलब्ध था। रिपोर्ट के मुताबिक जिन पार्टियों का विश्लेषण किया गया, उनमें बसपा इकलौती ऐसी पार्टी थी जिसने चुनाव के दौरान अपने केंद्रीय मुख्यालय या राज्य-इकाई स्तर पर इकट्ठा किए गए किसी भी फंड की जानकारी नहीं दी।

सांसदों की खरीद-फरोख्त पर कांग्रेस का गृह मंत्री पर हमला, कहा- भारतीय लोकतंत्र को कर रहे बर्बाद

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस ने बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह पर विपक्ष पर हमला करने और भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करने का आरोप लगाया। क्योंकि इस साल 17 अप्रैल को लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने में विफल रहने पर उन्हें मिली अपमानित हार का बदला लिया जा सके।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री लोकसभा में परिसीमन विधेयकों को पारित कराने में विफल रहने के बाद मिली अपनी अपमानजनक हार की भरपाई के लिए विपक्ष पर अपना हमला जारी रखे हुए हैं और भारतीय लोकतंत्र को नष्ट कर रहे हैं। रमेश ने एक्स पर आरोप लगाते हुए कहा, 'उनके प्रलोभन उन लोगों को आकर्षित कर रहे हैं जो महज दो साल पहले भाजपा विरोधी मजबूत एजेंडे पर चुने गए थे। अब वे भाजपा में शामिल हो रहे हैं। उन्हें कथित

तौर पर दिए जा रहे प्रोत्साहन चौंका देने वाले हैं।'

'अंतिम लक्ष्य में सफल नहीं होगे'

कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री एक पूरी तरह से निंदनीय अभियान चला रहे हैं, जो सुनियोजित है और म्यूचुअल फंड उद्योग की तरह, व्यक्तिगत जरूरतों के अनुरूप विभिन्न योजनाएं और उत्पाद पेश करता है। रमेश ने जोर देकर कहा 'उसकी दुष्टता की कोई सीमा नहीं है। लेकिन वह अपने अंतिम लक्ष्य में सफल नहीं होगे।'

संजय राउत ने क्या दावा किया?

उनकी यह टिप्पणी शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत के मंगलवार देर रात के उस दावे के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि 'महाराष्ट्र से सांसदों को खरीदने के लिए 15 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान' किया जा रहा है, जिससे पार्टी के लोकसभा सदस्यों के एक वर्ग के पाला बदलने की तेज अटकलों को और बल मिला है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) के सांसदों द्वारा तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के तर्ज पर संभावित विद्रोह की अटकलें तब और मजबूत हो गईं जब सत्तारूढ़ शिवसेना के नेता प्रताप सरनाइक ने असंतुष्टों का स्वागत करने और पार्टी बदलने की स्थिति में उन्हें प्राथमिकता देने का संकेत दिया।

जब शिवसेना (यूबीटी) के सांसद और उद्धव के करीबी राउत दिल्ली गए तो लोगों की भौंहें तन गईं, जिससे यह अटकलें लगने लगीं कि वे पार्टी के नौ सांसदों द्वारा अलग समूह बनाने के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर सकते हैं। एक्स पर देर रात एक पोस्ट में राउत ने कहा, 'अपना सपना पैसा.... पैसा! ऐसी जानकारी मिली है कि महाराष्ट्र से सांसदों को खरीदने के लिए आज रात 15 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान किया जाएगा। यह चौंकाने वाला और घृणित है।'

'मैं वापस आऊंगा' की अनसंग हीरो, जिसने कई फिल्मों को टेबल पर बैठ बना दिया मास्टरपीस

जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है, तो सबसे पहले उसके डायरेक्टर और लीड एक्टर्स की ही बात होती है। उसके बाद विलेन और प्रोड्यूसर पर लोग आते हैं। ज्यादा से ज्यादा सपोर्टिंग एक्टर्स तक ही लोग जानने की कोशिश करते हैं कि किसने पिक्चर में कौनसा रोल किया था। पर जब बात 'मैं वापस आऊंगा' जैसी फिल्मों की होती है, तो हर एक किरदार के बारे में जानना जरूरी होता है। वो भी जो पर्दे पर दिखा और वो भी जिसने पर्दे के पीछे से फिल्म में खूब मेहनत की। यहां जिस अनसंग हीरो की बात हो रही हैं, वो फिल्म की एडिटर Aarti Bajaj हैं। 53 साल की आरती बजाज ने ही खूबसूरती के साथ इस फिल्म को एडिट किया है, जिसके चलते एक-एक इमोशंस को लोग जी पाए। दरअसल वो अनुराग कश्यप की एक्स वाइफ हैं।

कई बार हम सिनेमा देखते हैं, तो एक शिकायत रहती है कि फिल्म स्क्रीन पर जैसे पेश की गई, उसमें कुछ कमी थी। उसके पीछे फिल्म एडिटर का भी बहुत बड़ा हाथ रहता है। खासकर जिन फिल्मों में फ्लैशबैक सीन्स भी बीच-बीच में दिखाए जाते हैं। उनके लिए बेहद अहम रहता है कि कहीं भी लोगों को ब्रेक या अधूरा फील न हो। आरती बजाज ने फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' के लिए टेबल पर बैठकर जो शानदार काम किया है, उसकी तारीफ बनती है। दरअसल उन्होंने अनुराग कश्यप की फिल्म 'पांच' से अपने एडिटिंग करियर की शुरुआत की थी।

दूसरी फिल्म से छा गईं थीं आरती

जिस दूसरी फिल्म को आरती बजाज ने एडिट किया, वो कश्यप की ही 'ब्लैक फ्राइडे' थी। जिसके लिए 2008 में स्टार स्क्रीन अवॉर्ड के लिए नॉमिनेट भी किया गया। उन्होंने इसके अलावा जिन फिल्मों पर काम काम किया है, उसमें रीमा कागती की 'हनीमून ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड', 'आमिर', इम्तियाज अली की 'जब वी मेट' भी शामिल है। यहां तक कि अनुराग कश्यप की 'देव डी', 'गुलाल', 'अगली', 'रमन राघव 2।0', 'मुक्काबाज', 'सेक्रेड गेम्स' और 'मनमर्जियां' को एडिट करने वाली भी आरती बजाज ही हैं। एक फिल्म को स्क्रीन पर कैसे पेश किया जाएगा, इसके पीछे डायरेक्टर का विजन जरूर होता है। लेकिन एडिटर चाहे, तो उसे बेहतर तरह से निखार सकता है। कुछ ऐसा ही काम आरती बजाज ने किया है।

इम्तियाज की इन फिल्मों के पीछे किसका हाथ?

यह तो अब आप जान चुके हैं कि इम्तियाज अली की 'मैं वापस आऊंगा' को आरती बजाज ने एडिट किया है। लेकिन यह सिर्फ एक ही फिल्म नहीं हैं, वो लंबे वक्त से उनके साथ जुड़ी हैं। जी हां, 2007 में आई 'जब वी मेट', 2009 की 'लव आज कल', 2011 की 'रॉकस्टार', 2014 की 'हाईवे', 2015 की 'तमाशा' और 2017 की 'जब हैरी मेट सेजल' पर भी आरती ने ही काम किया था।

जब 'रंगा-बिल्ला' के खौफ ने बॉबी देओल को घर में कैद कर दिया, लगाया गया था एक्टर पर कर्फ्यू

'रंगा-बिल्ला' केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस खौफनाक घटना का असर बॉबी देओल की जिंदगी पर भी पड़ा था। एक्टर ने खुद खुलासा किया था कि इस केस के बाद उनके पिता धर्मेंद्र ने उनकी सुरक्षा को लेकर इतनी सख्ती कर दी थी कि उन्हें घर से बाहर निकलने तक की आजादी नहीं थी।

फिल्मों के जरिए कई बार कुछ ऐसे केस लोगों के सामने पेश किए जाते हैं, जो कि एक वक्त पर खौफनाक दौर के समान था। हाल ही में अमेजन प्राइम की सीरीज 'राख' भी उन्हीं में से एक है। ये वेब सीरीज साल 1978 में घटित आपराधिक घटना 'रंगा बिल्ला' क्राइम केस से इंस्पायर है, इसने देश को झकझोर कर रख दिया था। लेकिन, इस केस से बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल का भी कनेक्शन है, जिसका खुलासा उन्हें एक पॉडकास्ट में किया था। एक्टर ने बताया था कि इस केस के चलते उनको घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं थी।

70 के दशक के सबसे चर्चित अपराधियों में शामिल रंगा और बिल्ला से था, जिनके नाम से उस दौर में पूरा देश कांप उठता था। सोनाली बेंद्रे और अली फजल स्टारर 'राख' भी इसी घटना से इंस्पायर है। लेकिन, 'रंगा बिल्ला' केस से बॉबी देओल की जिंदगी से जुड़ा भी एक ऐसा ही किस्सा है, जिसने उनके बचपन को गहराई से प्रभावित किया था। बॉबी देओल ने एक पुराने पॉडकास्ट में बताया था कि जब वो छठीं क्लास में थे, तो उनके एक करीबी दोस्त को किडनैप कर लिया गया था।

9 बजे के बाद रहता था कर्फ्यू

बॉबी देओल ने बताया कि कॉलेज के दौरान भी उन पर घर में कर्फ्यू लगा रहता था, उन्होंने कहा कि कॉलेज में जब मेरे दोस्त हाउस पार्टी करते थे, तो मुझे उसमें जाने की परमिशन भी नहीं थी। मुझे 9 बजे तक घर आना होता था। 'राख' की बात करें, तो इस सीरीज को प्रोसित रॉय ने डायरेक्ट किया था। अली फजल और सोनाली के अलावा सीरीज में आमिर बशीर , राकेश बेदी , दिव्येंदु भट्टाचार्य , आकाश मखीजा , रमनदीप यादव , दिव्या शर्मा और विवान शर्मा जैसे एक्टर्स शामिल

बॉबी देओल पर लगी थी रोक

एक्टर ने किस्सा आगे बताते हुए बताया कि उनके दोस्त की किस्मत अच्छी थी कि वो गलतफहमी के चलते किडनैपर के चंगुल से निकलकर भाग आया। हालांकि, इस दौरान किडनैपर ने एक्टर के दोस्त से उसके स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के बारे में पूछा था। इस दौरान उसने बॉबी देओल का नाम भी ले लिया था। इसके बाद से ही बॉबी देओल पर रोक लगनी शुरू हो गई। एक्टर ने कहा, 'मेरी सिक्योरिटी की वजह से उस इंसिडेंट के बाद पापा ने मुझे घर नहीं छोड़ने दिया। मैं उस दिन स्कूल से आया, बस उसके बाद तो मैं साइकल चलाना भी घर में ही सीखता था।'

अवतार: फायर एंड ऐश की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, 24 जून से डिज्नी+ पर देख सकेंगे जेम्स कैमरून की फिल्म

जेम्स कैमरून की साइंस फिक्शन फिल्म अवतार: फायर एंड ऐश 19 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की। वहीं, दर्शक लंबे समय से इस फिल्म की ओटीटी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फाइनली अब ये फिल्म ओटीटी पर दस्तक देने जा रही है। चलिए यहां जानते हैं ये फिल्म किस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कब और कहां रिलीज होगी?

अवतार: फायर एंड ऐश फाइनली अब ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है। मेकर्स ने ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी+ को इस फिल्म के राइटर्स बेच दिए हैं। फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट भी कंफर्म हो गई है। इस फिल्म को आप 24 जून, 2026 से डिज्नी+ पर स्ट्रीम कर सकते हैं। मेकर्स ने इसकी जानकारी देते हुए लिखा, अवतार: फायर एंड ऐश सिर्फ डिज्नी + पर 24 जून को स्ट्रीम करें।

ये फिल्म पैंडोरा की दुनिया में चल रहे संघर्ष को एक नए स्तर पर ले जाती है। इस बार इंसानों और नावी के बीच का टकराव और भी गहरा और खतरनाक हो गया है। कहानी में कुछ नए कबीले और किरदार भी जोड़े गए हैं। फिल्म में विजुअल्स के साथ-साथ इमोशनल एंगल पर भी काफी काम किया गया है, जो दर्शकों को फिल्म से जोड़े रखता है। कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में सैम वर्थिंगटन, जो साल्डाना, सिगर्नी वीवर और स्टीफन लैंग जैसे सितारे नजर आए।

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, अवतार: फायर एंड ऐश ने दुनियाभर में करीब 13,915 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। वहीं, इस फिल्म का बजट लगभग 3,200 करोड़ रुपये है।

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक प्रभात पांडेय द्वारा साई ऑफसेट प्रिंटर्स 40, वासुदेव भवन कैसरबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 2/74, विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ से प्रकाशित।
शाखा कार्यालय: S-15/109, सेक्टर -15, इंदिरा नगर, लखनऊ। समस्त लेख, रचनाओं एवं विज्ञापन में लेखन और विज्ञापनदाताओं के अपने विचार हैं। इसके लिए आर्यावर्त क्रांति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश ही होगा। RNI No: UPHIN/2014/57034 Website: aryavartkranti.com
*सम्पादक: प्रभात पांडेय सम्पर्क: 9839909595, 8765295384 Email: aryavartkrantidainik@gmail.com